2017-18 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का सिंहावलोकन

01
अध्याय

वर्ष 2016-17 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी वृद्धि की ओर अग्रसर हुई, जो केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2017-18 में 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह हालिया घटनाक्रमों के आधार पर वर्तमान में पूर्वानुमानित 2017-18 में 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के दायरे से थोड़ा सा कम है। 2017-18 के लिए इस कमतर वृद्धि के साथ भी, 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए जीडीपी वृद्धि का औसत 7.3 प्रतिशत रहा है, जो विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। यह तथ्य कि यह वृद्धि कम मुद्रास्फीति, बेहतर चालू खाता शेष और जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी के चलते हासिल की गई, इसे और अधिक सराहनीय बनाता है। जीएसटी (माल और सेवा कर) शुरू करने के अलावा, इस वर्ष बैंकों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित समस्याओं के समाधान, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक उदार बनाने आदि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, इस प्रकार सुधारों की गति और तेज की गई। दो वर्षों के लिए ऋणात्मक स्थिति में रहने के बाद, 2016-17 में निर्यात वृद्धि में दुबारा उछाल आया और 2017-18 में इसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 414 बिलियन अमरीकी डालर के आस-पास रही।

कुछ देशों में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और अभी यह देखना बाकी है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके अलावा, कच्चे तेल की औसत कीमतें (भारतीय समूह) अब तक 2017-18 (जनवरी 2018 के मध्य में) वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत बढ़ी हैं। यदि हम हालिया प्रवृत्ति के अनुसार देखें तो मौजूदा वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत प्रति बैरल 56-57 अमरीकी डालर के आस-पास रहेगी और 2018-19 में और 10-15 प्रतिशत बढ़ सकती है। आने वाले वर्ष में इनमें से कुछ कारकों से जीडीपी की वृद्धि दर मन्द हो सकती है। तथापि, चूंकि 2018 में वैश्विक वृद्धि में साधारण सुधार होने की संभावना है, अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी में अधिक स्थिरता की आशा, निवेश स्तर में संभावित सुधार और चालू अवसंरचनात्मक सुधार उच्चतर वृद्धि में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर, देश के आर्थिक प्रदर्शन में 2018-19 में सुधार आना चाहिए।

2017-18 में जीडीपी में वृद्धि

1.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का औसत 2014-15 और 2016-17 के बीच 7.5 प्रतिशत से अधिक रहने से, इस मानदण्ड पर भारत को विश्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों में गिना जा सकता है। पिछले 3 वर्षों के वैश्विक विकास औसत से यह वृद्धि 4 प्रतिशतांक से अधिक है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों द्वारा हासिल की गई औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है (चित्र 1)। यद्यपि 2017-18 में वृद्धि कम होकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है, जो 4 वर्ष के औसत को 7.3 प्रतिशत पर ला देगी। भारत की जीडीपी वृद्धि की गाथा में जो मोटे तौर पर विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में अधिक होने की है, कोई फेर-बदल नहीं होगा। यह वृद्धि पिछले 3 वर्षों की वैश्विक औसत वृद्धि से लगभग 4 प्रतिशतांक अधिक है और उभरते बाजारों एवं विकासशील देशों द्वारा हासिल औसत वृद्धि से लगभग 3 प्रतिशतांक अधिक है (चित्र 1)।

सारणी 0.1: मुख्य संकेतक

सारणी- प्रमुख संकेतक	ईकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी और संबंधित संकेतक					
जीडीपी (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	10536984	11381002	12189854पीई	12985363एई
वृद्धि दर	%	7.5	8.0	7.1	6.5
आधार कीमतों पर जीवीए (2011-12 कीमतों पर)	₹ करोड़	9719023	10490514	11185440पीई	11871321एई
वृद्धि दर	%	7.2	7.9	6.6	6.1
बचत दर	% of जीडीपी	33.1	32.3	एनए	एनए
पूंजी निर्माण (दर)	% of जीडीपी	34.4	33.3	एनए	एनए
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर)	₹	86454	94130	103219	111782
उत्पादन					
खाद्यान्न	मिलियन टन	252.0	251.6	275.7*	134.7#
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वृद्धि)	%	4.0	3.3	4.6	3.2जी
बिजली उत्पादन (वृद्धि)	%	14.8	5.7	5.8	4.9जी
कीमतें					
मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) (औसत)	% परिवर्तन	1.2	-3.7	1.7	2.9सी
मुद्रास्फीति (सीपीआई) (संयुक्त) (औसत)	% परिवर्तन	5.9	4.9	4.5	3.3सी
वैदेशिक क्षेत्र					
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% परिवर्तन	-1.3	-15.5	5.2	12.1सी
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% परिवर्तन	-0.5	-15.0	0.9	21.8सी
मौजूदा लेखा शेष (कैब)/जीडीपी	%	-1.3	-1.1	-0.7	-1.8डी
विदेशी मुद्रा भण्डार	अमेरिकी डालर बिलियन	341.6	360.2	370.0	409.4ई
औसत विनिमय दर	₹ /अमेरिकी डालर	61.14	65.46	67.07	64.49सी
मुद्रा और ऋण					
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	10.9	10.1	10.1	10.5एफ
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	% परिवर्तन	9.0	10.9	8.2	9.3जी
राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)					
सकल राजकोषीय घाटा	जीडीपी का %	4.1	3.9	3.5	3.2बीई
राजस्व घाटा	जीडीपी का %	2.9	2.5	2.1	1.9बीई
प्राथमिक घाटा	जीडीपी का %	0.9	0.7	0.4	0.1बीई

टिप्पणीयां :

एनए-उ.न.

पीई-अ.अ.

एई-प्र.अ.अं.

क-आधार (2011-12=100)

ख-अप्रैल-अक्तूबर-2017

ग-अप्रैल-दिसंबर-2017

घ-अप्रैल-नवंबर-2017

ङ-अप्रैल-सितंबर-2017

च-बजट अनुमान

छ-अनंतिम (वास्तविक) (गैर लेखांकित)

चित्र 1. 2014-17 के दौरान जीडीपी की औसत तुलनात्मक वृद्धि (प्रतिशत)

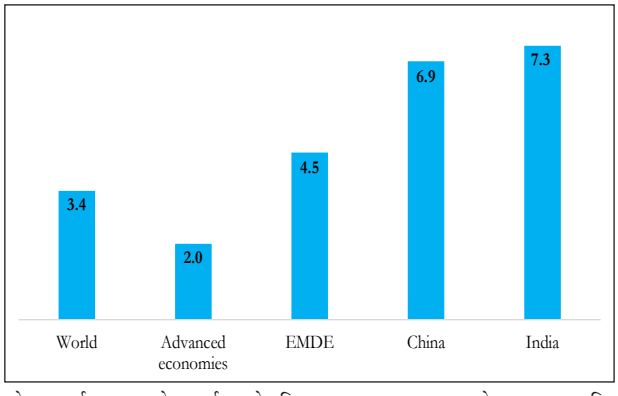

स्रोत: आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनामिक आउट लुक डाटा बेस पर आधारित (अक्टूबर 2017)

1.2 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार सतत बुनियादी मूल्य पर सकल मूल्यवर्द्धन वृधि दर 2017-18 में 6.1 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2017-18 में यह 6.6 प्रतिशत थी यह कृषि और सम्बद्ध तथा उद्योग के क्षेत्र में कम वृद्धि के कारण हुई थी। आशा है कि इनमें क्रमश: 201 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। 2017-18 में 2016-17 के 7.7 प्रतिशत की तुलना में सेवा क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत वृद्धि हो सकती हैं। सेवा क्षेत्र के भीतर केवल लोकप्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2017-18 में गिर सकती है। उन्नत देश उभरते बाजार और विश्व भारत चीन विकासशील देश

1.3 2012-13 में जीडीपी में 5.5% की निम्न वृद्धि से अगले 3 वर्षों तक लगातार सुधार हुआ और 2015-16 में यह शिखर पर पहुंच गयी, विशेष रूप से चौथी तिमाही में जब इसमें 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई (2015-16 की चौथी तिमाही में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में भी काफी वृद्धि हुई) बहरहाल, 2016-17 की प्रथम तिमाही से वृद्धि में कमी आने लगी। 2016-17 की चौथी तिमाही में जीडीपी और जी वी ए में वृद्धि और कम होकर क्रमश: 6.1%, 5.6% रह गई। 2017-18 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में वृद्धि और कम होकर 5.7% हो गई। तथापि 2017-18 की दूसरी तिमाही से जीडीपी वृद्धि की गिरावट की प्रवृत्ति में उलट-फेर हुआ और बढ़कर 6.3% हो गई। 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी और जीवीए की मामूली वृद्धि में तेजी आई और क्रमश: 9.4 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत पर आ गई। (चित्र 2)

चित्र 1. वास्तविक मूल्य वर्द्धित और जीडीपी में वृद्धि (प्रतिशत)

आधार मूल्य पर जीवीए	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (1st AE)
कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	**-0.2**	**0.7**	**4.9**	**2.1**
उद्योग	**7.5**	**8.8**	**5.6**	**4.4**
खनन तथा खननकार्य	11.7	10.5	1.8	2.9
विनिर्माण	8.3	10.8	7.9	4.6
विद्युत गैस एवं जलआपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाएं	7.1	5.0	7.2	7.5
निर्माण	4.7	5.0	1.7	3.6
सेवाएं	**9.7**	**9.7**	**7.7**	**8.3**
व्यापार, होटल, परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण से संबधित सेवाएं	9.0	10.5	7.8	8.7
वित्तीय, स्थावर संपदा एवं पेसेवर सेवाएं	11.1	10.8	5.7	7.3
लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं	8.1	6.9	11.3	9.4
आधार मूल्य पर जीवीए	**7.2**	**7.9**	**6.6**	**6.1**
बाजार मूल्य पर जीडीपी	**7.5**	**8.0**	**7.1**	**6.5**

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त आकड़ो पर आधारित

चित्र 2. 2011-12 कीमतों पर जीडीपी और जीवीए में वृद्धि (प्रतिशत)

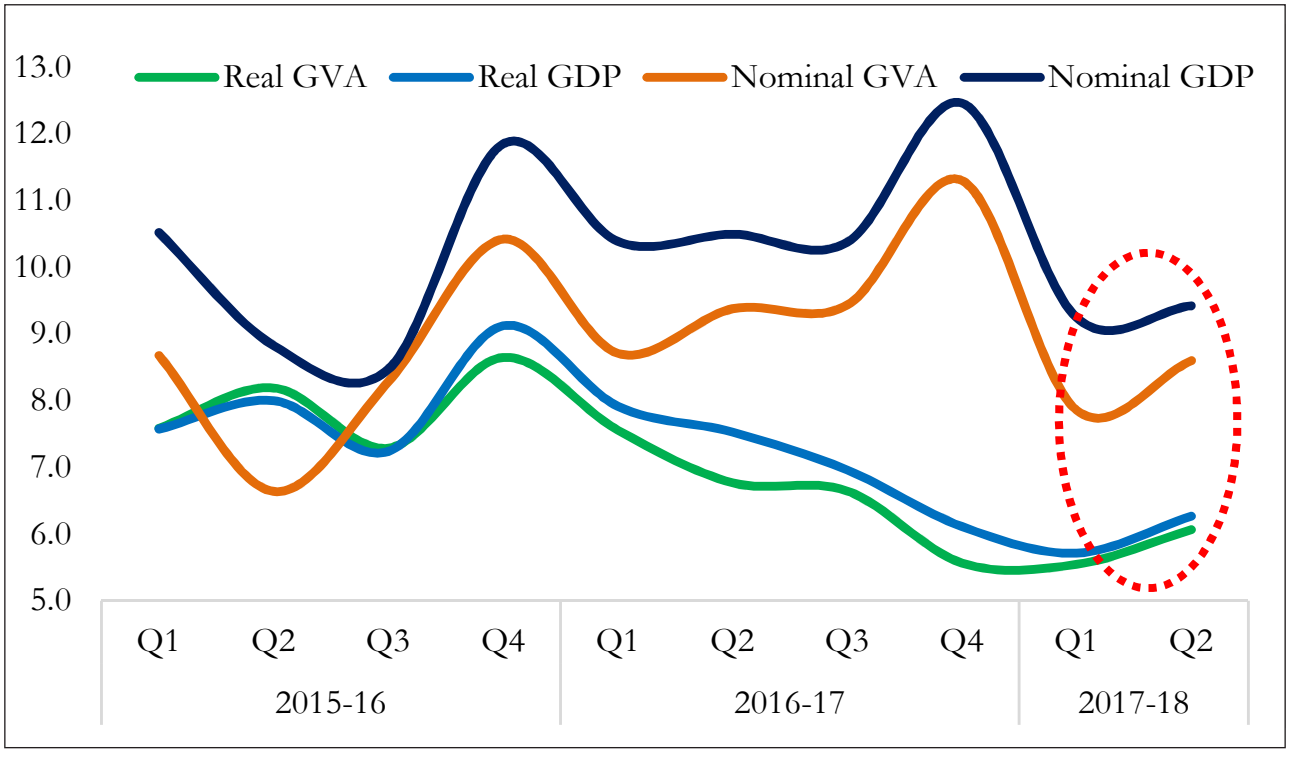

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.4 प्रथम अग्रिम अनुमानों के तहत, 2017-18 में जीडीपी में वृद्धि 6.5% होने की आशा है, जबकि आधार कीमतों पर वास्तविक जीवीए में 6.1% वृद्धि होने की आशा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी और जीवीए में वृद्धि क्रमश: 6.0% और 5.8% होने से, वर्ष की दूसरी तिमाही में अंतर्निहित वृद्धि क्रमश: 7% और 6.4% बैठती है, जोकि अर्थव्यवस्था में बेहतरी को दर्शाता है, जिसका श्रीगणेश 2017-18 की दूसरी छिमाही में ही हो चुका था। प्रमुख वृहत संकेतक जैसे सकल नियत निवेश और निर्यातों में भी 2017-18 के पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में वृद्धि तीव्रतर होने की आशा है।

1.5 हालिया वर्षों में वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी वृद्धि की खाई में भी कमी आई है। 2012-13 और 2014-15 के दौरान वास्तविक जीडीपी में औसतन वृद्धि 6.4% रही, इसी अवधि में मौद्रिक वृद्धि 12.5% थी, इसकी तुलना में 2015-16 से 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के दौरान वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी में औसत वृद्धि क्रमश: 7.2% और 10.1% होने की संभावना है, जोकि बाद की अपेक्षा पूर्वावधि में उच्चतर अंतर को दर्शाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं: पूर्वावधि में मुद्रास्फीति उत्तरवर्ती अवधि की तुलना में काफी अधिक थी।

1.6 2016-17 में जीडीपी में मामूली वृद्धि 11% होने की संभावना है और 2017-18 में निम्नतर वास्तविक वृद्धि और अपस्फीतक के कम अधिमूल्य के कारण 2017-18 में जीडीपी 9.5% होने की आशा है। इन दो वर्षों में मौद्रिक जीवीए की वृद्धि 9.7% और 9.0% होने की आशा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मौद्रिक जीवीए और जीडीपी की वृद्धि में अंतर भी बढ़ा है। यह जीडीपी में निवल अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि दर्शाता है।

मुख्य क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि

1.7 जैसी कि अपेक्षा थी सामान्य बारिश होने के कारण कृषि क्षेत्र में पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय उच्च वृद्धि पर देखने को मिली। खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह अनुमान

लगाया गया था कि वर्ष 2016-17 में खाद्यान्नों की पैदावार 275.7 मिलियन टन होगी और खाद्यान्न तथा दालें, दोनों का उत्पादन रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाएगा। अधिकांश अन्य फसल और गैर-फसल कृषि क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2016-17 में लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों ने भी दो अंकों में वृद्धि दर्ज की जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन तथा बकाया राशियों के उच्च भुगतान के कारण थी। तथापि, पिछले वित्त वर्ष में उद्योग सेक्टर की वृद्धि में 3 प्रतिशत बिंदु की कमी आई।

1.8 वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में जीवीए वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, दोनों तिमाहियां अलग-अलग तस्वीर पेश कर रही थीं। जीवीए में पिछली कुछ तिमाहियों में देखी गई कमी की प्रवृत्ति वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में रूक गई जिसमें वही वृद्धि दर दर्ज की गई जो वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में थी। 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह कमी की प्रवृत्ति की स्थिति विपरीत हो गई और जीवीए वृद्धि 6.1 प्रतिशत हो गई, यह पहली तिमाही की तुलना में 0.5 प्रतिशत बिंदुओं का सुधार था। यह मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र के कारण हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार नजर आया जो पहली तिमाही में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के दूसरी छमाही के लिए जीवीए की अन्तर्निहित वृद्धि 6.4 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों नामत: कृषि और संबद्ध उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में दूसरी छमाही में अन्तर्निहित वृद्धि क्रमश: 2.2 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत रही है जो 2017-18 की पहली छमाही से बेहतर है (चित्र 3)। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2017-18 के पहली छमाही, में 4.0 प्रतिशत से सुधर कर दूसरी छमाही में 5.1 प्रतिशत होने की आशा है। व्यापार, परिवहन, होटल, भंडारण, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाओं का सेक्टर एकमात्र वह सेक्टर है जिसके वर्ष 2017-18 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में वृद्धि में कमी आने की संभावना है। (चित्र 3)

चित्र 3: वर्ष (2011-12) के बुनियादी मूल्यों पर जीवीए में छमाही वृद्धि

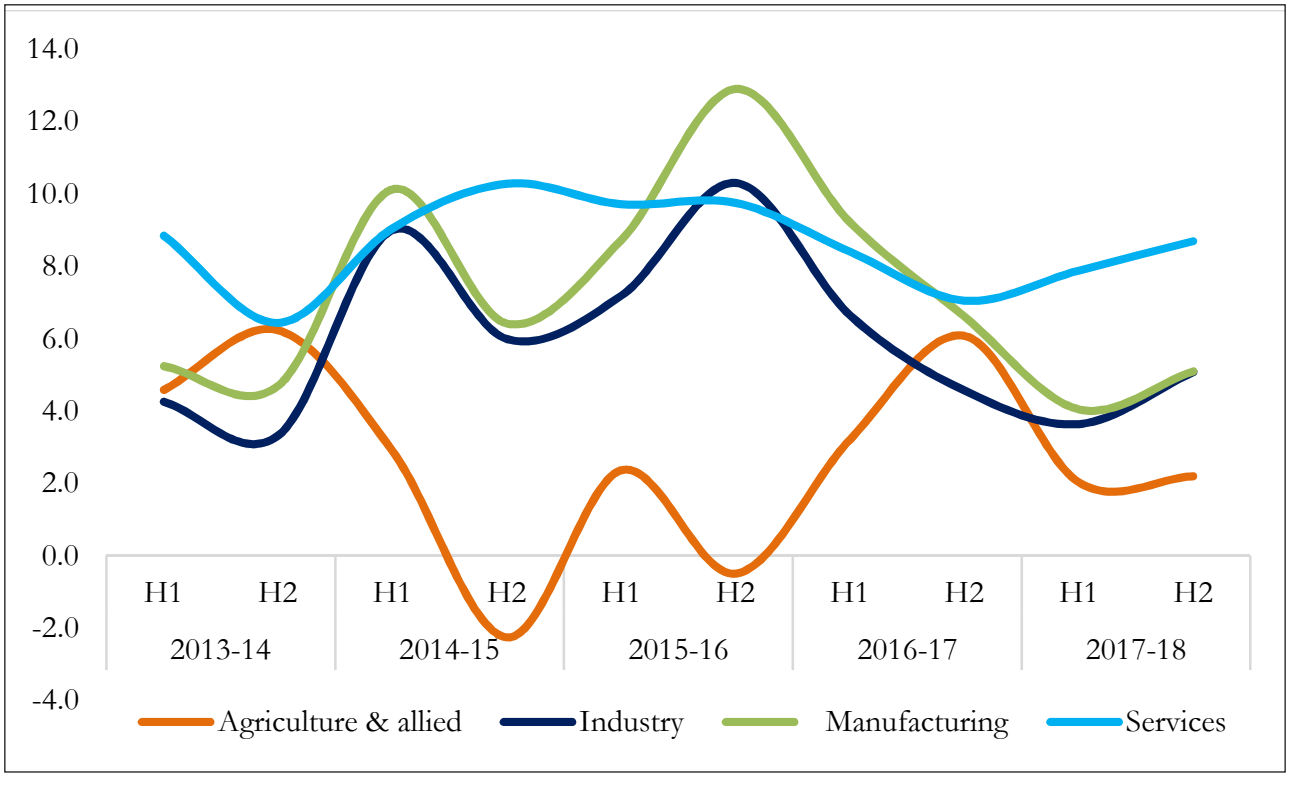

स्रोत: सीएसओ से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित।

टिप्पणी : 2017-18 की दूसरी छमाही एई और 2017-18 की दूसरी तिमाही अनुमानों पर आधारित है।

1.9 वर्ष 2016-17 में जीवीए वृद्धि की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि दो क्षेत्रों (सेक्टरों) नामत: कृषि और संबद्ध 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' ने अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि में लगभग एक तिहाई अंशदान किया इन दोनों क्षेत्रों के अधिक अंशदान का कारण वर्ष 2016-17 में इन दोनों सेक्टरों मे उच्च वृद्धि का होना था। इन क्षेत्रों ने 2012-13 से 2015-16 की अवधि (चित्र 4) के बीच जीवीए वृद्धि के लगभग 1/6 भाग का औसत अंशदान किया। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच सेवाओं (लोक प्रशासन, रक्षा आदि को छोड़कर) कुछ जीवीए वृद्धि का लगभग 57 प्रतिशत योगदान किया। वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवा सेक्टर में कम वृद्धि के कारण 2016-17 में कम होकर यह 41 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2016-17 में लोक प्रशासन रक्षा तथा अन्य सेवाओं की कुल वृद्धि का योगदान, वर्ष 2012-13 और 2015-16 के बीच औसत योगदान का लगभग दोगुना था। दूसरी ओर, 2013-14 से सकल मूल्यवर्धन वृद्धि में वित्तीय सेवाओं, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं के योगदान में लगातार गिरावट आई (यह वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान 32.7 प्रतिशत औसत से घट कर 2016-17 में 18.8 प्रतिशत रह गयी।

1.10 वर्ष 2017-18 में सकल मूल्यवर्द्धन वृद्धि में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के बीच में उलट गई, वर्ष 2017-18 में 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं' के योगदान में कुछ गिरावट आई क्योंकि इस सेक्टर की वृद्धि की गति धीमी हुई। वर्ष 2017-18 में विकास में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की कमी आई जो मुख्यत: पहली छमाही और विशेष रूप से पहली तिमाही में इस क्षेत्र हुई अपेक्षाकृत कम वृद्धि के करणा रहा।

तिमाहीवार सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि

1.11 पिछली कुछ तिमाहियों में जीवीए वृद्धि कम रहने के बाद यह वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 6.1 होंगे। वर्ष 2015-16 की आखिरी तिमाही से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की जीवीए वृद्धि की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति 2016-17 की चौथी तिमाही से पलट गई। वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में उद्योग की वृद्धि में गिरावट आना शुरू हो गई थी और चौथी तिमाही में विशेषरूप से यह वृद्धि कम थी। हालांकि 2017-18 की दूसरी तिमाही में उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। 2015-16 की चौथी तिमाही से बाद की प्रत्येक तिमाहियों में विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में गिरावट आई, (2016-17 की तीसरी तिमाही को छोड़कर) 2017-18 की पहली तिमाही तक जब वह 1.2

चित्र 4: सकल मूल्य वर्धन वृद्धि में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

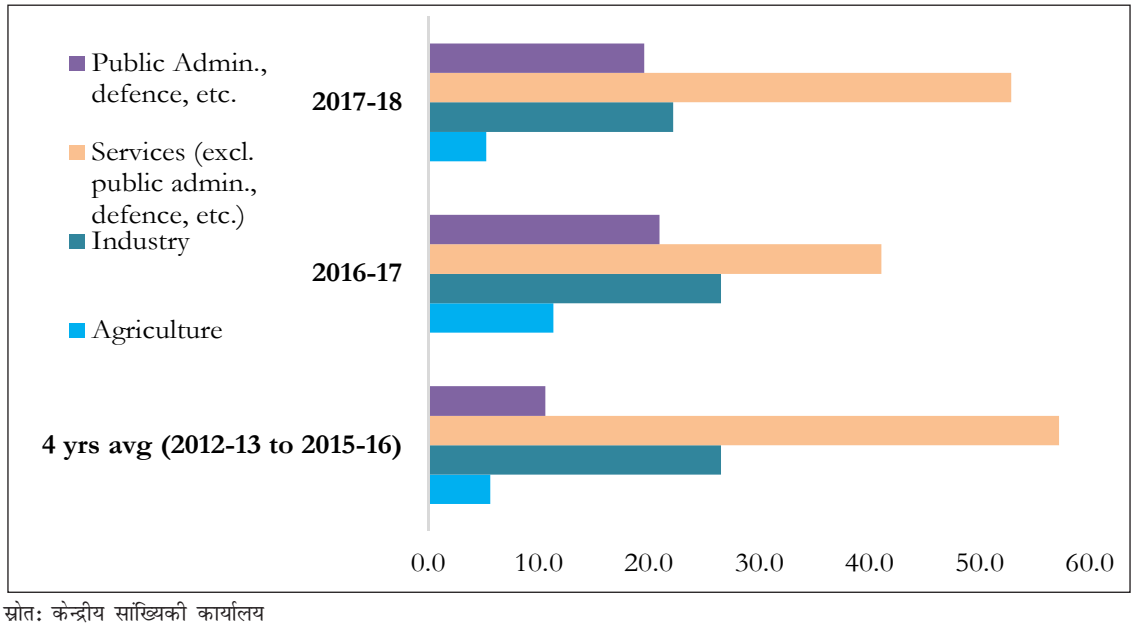

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

[1] अन्य सेवाओं में समुदाय सेवाएं जैसे-कोचिग सेंटरए शिक्षा, शिक्षा, वैयक्तिक सेवाएं आदि शामिल हैं।

प्रतिशत पर पहुंच गई थी। 2017-18 की दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत पर इसमें तेजी से सुधार हुआ। औद्योगिक विकास इतना धीमा क्यों रहा होगा इसका एक कारण क्रेडिट वृद्धि में आई कमी हो सकती है। वर्ष 2015-16 में उद्योग में नियोजित किए गए क्रेडिट वृद्धि (बकाया) में उल्लेखनीय रूप से आई कमी 2016-17 में नकारात्मक हो गई, और 2017-18 की पहली छमाही में ऐसी ही बनी रही। यह कहना कठिन है कि क्या यह गिरावट क्रेडिट की कम मांग के कारण थी अथवा क्या यह अनर्जक आस्तियों (एनपीए), की समस्या को पहचानने के कारण हैं, जिन्होंने उधार देने में बैंकों का और अधिक सचेत बनाया होगा, तथापि, 24 नवम्बर 2017 को औद्योगिक क्षेत्र का बकाया क्रेडिट 25 नवम्बर 2016 के बकाया क्रेडिट से 1 प्रतिशत दर 2016-17 की तीसरी और चौथी तिमाही की तुलना में 2017-18 की पहली दो तिमाहियों में कम रही है। (सारणी 2)।

प्रति व्यक्ति आय

1.13 वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय (2011-12 के स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापित) किसी भी देश के लोगों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह आय 2015-16 के 77,803 रुपए से बढ़कर 2017-18 में 86,660 रुपए हो जाने की संभावना है जो 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की द्योतक है। मौद्रिक रूप में इसमें औसतन 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई और यह 2015-16 के 94,130 रुपए से बढ़कर 2017-18 में 111,782 रुपए हो गई।

सारणी-1 तिमाहीवार वास्तविक जीवीए और जीडीपी वृद्धि

क्षेत्र	2016-17				2017-18	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	7.6	6.8	6.7	5.6	5.6	6.1
कृषि और सहबद्ध क्षेत्र	2.5	4.1	6.9	5.2	2.3	1.7
उद्योग	7.4	5.9	6.2	3.1	1.6	5.8
जिसमें (विनिर्माण)	10.7	7.7	8.2	5.3	1.2	7.0
सेवाएं	9.0	7.8	6.9	7.2	8.7	7.1
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	7.9	7.5	7.0	6.1	5.7	6.3

स्रोत: सीएसओ से प्राप्त आकड़ों पर आधारित

अधिक था। यद्यपि, निर्माण क्षेत्र में वर्धित मूल्य मेंप्रसारण से संबधित 2016-17 की चौथी तिमाही में कमी हुई थी, फिर इसमें आगामी तिमाहियों में सुधार हुआ। 1.12 सेवा क्षेत्र का विकास जो 2016-17 की तीसरी तिमाही में कम हो गया था, 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' के क्षेत्र में वास्तविक संदर्भ में 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ही मुख्यतया चौथी तिमाही में जरा सा बढ़ गया। व्यापार, परिवहन, भण्डारण, संचार आदि' क्षेत्रों में विकास, आंशिक रूप से उच्च आधार प्रभाव (वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में इस क्षेत्र का विकास 12.8 प्रतिशत था) के कारण कम था। वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में 6.5 प्रतिशत था। 'वित्तीय सेवाएँ, स्थावर संपदा तथा पेशेवर सेवाएँ तथा 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं' के क्षेत्र में उच्च वृद्धि के बल पर-2017-18 की पहली छमाही तथा 2016-17 की दूसरी छमाही में सेवाओं की वृद्धि पर में कुछ सुधार हुआ है। दूसरी तरफ, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि

सकल घरेलू उत्पाद और इसके घटक

1.14 उपभोग व्यय 2012-13 और 2015-16 के बीच कुल जीडीपी वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत रहते हुए अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रेरक रहा है। यह अंशदान बढ़कर 2016-17 में 95 प्रतिशत से अधिक हो गया जिसकी वजह निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) दोनों में हुई उच्च वृद्धि को माना जा सकता है। विशेषकर, जीएफसीई की वृद्धि 2012-13 से 2015-16 के दौरान 3.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में वास्तविक संदर्भ में लगभग 21 प्रतिशत बढ़ी। इसकी वजह मुख्यत: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान है। पीएफसीई और जीएफसीई दोनों की वृद्धि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कम हाने की संभावना है। जीडीपी में निवेश का हिस्सा और विशेषकर

स्थिर निवेश का हिस्सा 2011-12 और 2016-17 के बीच निरंतर गिरता रहा। जहां 2011-12 के स्थिर निवेश जीडीपी का 34.3 प्रतिशत था, यह गिरकर 2016-17 में 27.1 प्रतिशत रह गया। हालांकि, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में स्थिर निवेश के तीव्र दर पर बढ़ने की संभावना है (जो निवेश में कुछ सुधार इंगित करता है), फिर भी यह जीडीपी में स्थिर निवेश के हिस्से में और गिरावट रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। माल और सेवाओं का निर्यात 2014-15 में लगभग गतिरुद्ध रहने और 2015-16 में गिरने के बाद 2016-17 में बढ़ना शुरू हुआ। आयातों में भी वृद्धि हुई लेकिन धीमी रफ्तार पर, फिर भी इससे 2016-17 में चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिली। वर्ष 2017-18 में निर्यातों में 4.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, वहीं आयातों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से वृद्धि होने की संभावना हैं। परिणामात्मक जीडीपी में माल और सेवाओं के निवल निर्यात का हिस्सा (जैसाकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिखाया गया है) 2016-17 के (-) 0.7 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में (-) 1.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

अंतिम उपभोग व्यय

1.15 वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच 6 वर्षों में, कुल जीडीपी में पीएफसीई का औसत हिस्सा 57.5 प्रतिशत रहा और इस अवधि में इसकी वृद्धि औसतन 6.8 प्रतिशत रही। पीएफसीई जीडीपी की वृद्धि का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक रहा है और विशेष रूप से ऐसा 2016-17 में हुआ है जब पीएफसीई ने जीडीपी वृद्धि के लगभग दो तिहाई का योगदान किया। इसके अतिरिक्त, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) का योगदान 29 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, जीडीपी वृद्धि में पीएफसीई और जीएफसीई का योगदान क्रमशः 54.3 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। जहां पीएफसीई का योगदान 2011-12 से 2015-16 में हासिल औसत स्तरों पर लौट आया, वहीं जीएफसीई का योगदान उस औसत से अधिक बना रहा है।

1.16 पीएफीसीई का आगे ब्यौरा (केवल 2015-16 तक उपलब्ध है) दर्शाता है कि गैर-टिकाऊ वस्तुओं का हिस्सा (जिसमें अधिकांश खाद्य पदार्थ है) 2011-12 और 2015-16 के बीच (2013-14 के बाद) (चित्र 5) कुछ-कुछ गिर गया। यह गिरावट प्रत्याशित है क्योंकि आय स्तरों में वृद्धि के साथ खाद्य उत्पादन का हिस्सा, विशेषकर खाद्यान्नों के हिस्से, में गिरावट का रुझान रहता है (एंजल का लोचशीलता पर आधारित विश्लेषण, बाक्स 1.1 देखें)। स्थिर कीमतों के संदर्भ में इस हिस्से में अधिक तीव्र गिरावट इस अवधि में अन्य मद समूहों की तुलना में कुछ खाद्य उत्पादों जैसे मछली और सी-फूड, फल इत्यादि के संबंध में अपस्फीतिकारक के अपेक्षाकृत कम मूल्य (अर्थात अधिक मूल्य वृद्धि) से

चित्र 5: वर्तमान मूल्यों पर निजी उपयोग व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)

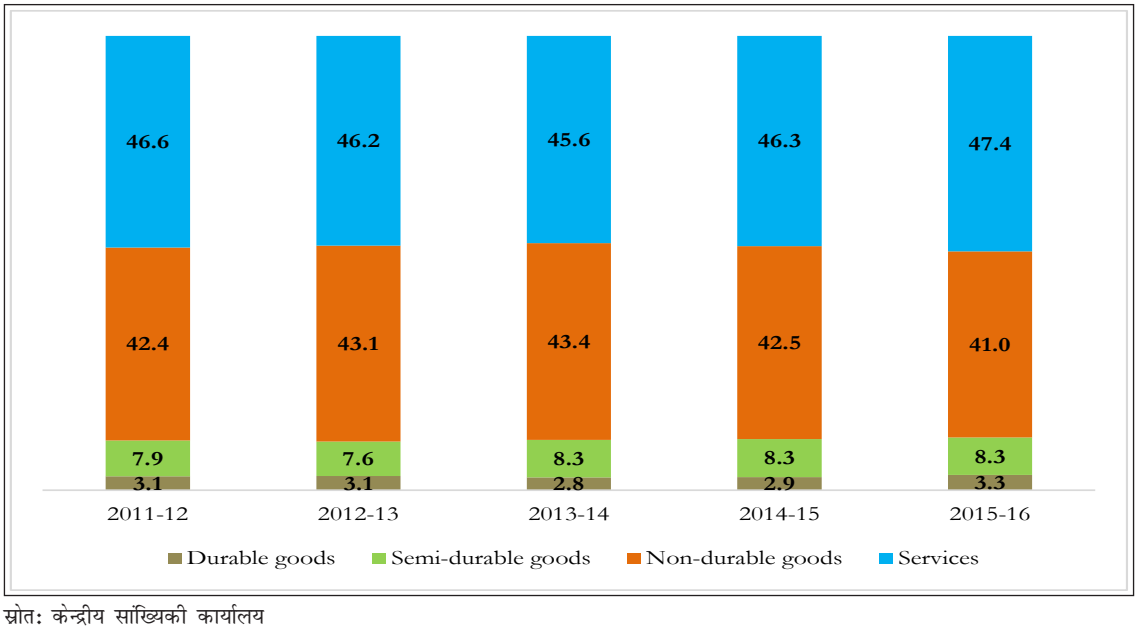

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

बाक्स 1.1 पीएफसीई के संबंध में मुख्य वस्तु समूहों की एंजल की लोचशीलता

उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने का एक तरीका एंजल का लोचशीलता है। नीचे दी गई सारणी में चुनिंदा वस्तु समूहों के लिए एंजल की लोचशीलता दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि यहां परिकलित एंजल की लोचशीलता 2011-12 के स्थिर कीमतों पर समग्र निजी अंतिम उपभोग व्यय के प्रति किसी विशेष वस्तु समूह के निजी अंतिम उपभोग व्यय की अनुक्रियाशीलता दर्शाती है।

घरेलू बाजार में निजी अंतिम खपत व्यय का सीएजीआर और एंजल लोचशीलता

मद का वर्णन	सीएजीआर 2011-12 से 2015-16	पीएफसीई के संदर्भ में लोचशीलता
भोजन और गैर-एल्कोहलिक पेय-पदार्थ	4.1	0.61
कपड़ा और फुटवीयर	9.6	1.44
आवास, पानी, बिजली, गैस तथा अन्य ईंधन	5.2	0.78
साज-सज्जा, घरेलू उपस्कर और रखरखाव,	9.3	1.39
स्वास्थ्य	13.1	1.95
परिवहन	6.5	0.98
संचार	7.3	1.09
शिक्षा	6.3	0.93
घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय	6.7	

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सीएसओ

जैसीकि आशा थी, भोजन संबंधी मदों की एंजल लोचशीलता काफी कम है, जो इस परिकल्पना की पुष्टि करती है कि जैसे आय का स्तर बढ़ता है, भोजन पर व्यय समानुपात से कम बढ़ता है। भोजन के अंतर्गत अंडा, मॉस और मछली, सब्जी आदि जैसे उत्पादों की लोचशीलता ब्रैड, अनाज और दालों जैसे मदों से अधिक है। जबकि स्वास्थ्य पर व्यय की लोचशीलता एक से काफी अधिक है, परंतु शिक्षा पर यह आश्चर्यजनक रूप से एक से थोड़ी कम है।

जुड़ी है।

बचत और निवेश

1.17 इस तथ्य के बावजूद, कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2014-15 और 2017-18 के बीच 4 वर्षों में भारी वृद्धि दर्ज की है, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की कहानी दिलासा देने वाली नहीं रही है। अर्थव्यवस्था में निवेश दर (सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में सकल पूंजी निर्माण (जीएसएफ)) 2011-12 और 2015-16 के बीच लगभग 5.6 प्रतिशत बिंदु कम हुई है। जैसाकि सारणी 3 में देखा जा सकता है, वर्ष 2013-14 में मुख्य कमी हुई हैं जब निवेश दर लगभग 5 प्रतिशत बिंदु कम हो गयी थी। यह बहुत से कारकों के कारण थी जैसे भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयाँ, विलंबित और रुकावट वाली पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियाँ, अवसंरचना क्षेत्र में समस्याएँ आदि। यद्यपि ऐसी बहुत सी समस्याएँ विद्युत की बेहतर स्थिति बनाकर, अवसंरचना संबंधी अड़चनों को कम करके दूर कर दी गई है, फिर भी निवेश दर (मुख्यत: स्थिर निवेश) नहीं बढ़ी है। वर्ष 2011-12 और 2013-14 के बीच बचत दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल बचत) भी लगभग ढाई प्रतिशत बिंदु कम हुई हैं तथा उसके बाद कमोबेश स्थिर रही है। बचत दरों की तुलना में निवेश दर में तीव्र गिरावट के कारण 2013-14 से 2015-16 तक चालू खाता घाटे का स्तर (बचत-निवेश अंतर) अपेक्षाकृत

सारणी 2: बचत, निवेश दर (प्रतिशत में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
निवेश दर	39.0	38.7	33.8	34.4	33.3
बचत दर	34.6	33.9	32.1	33.1	32.3
एस-आई अंतर	-4.3	-4.8	-1.7	-1.3	-1.0

स्रोत: सीएसओ के आँकड़ों पर आधारित।

कम रहा है।

बचत

1.18 अर्थव्यवस्था में बचत सामान्य प्रशासन सहित परिवारों, निजी कारपोरेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से होती है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत के अनुरूप 2011-12 तथा 2015-16 के बीच जीडीपी के अनुपात के रूप में परिवार क्षेत्र की बचत सामान्यत: कम हुई है यह जीडीपी के 23.6 प्रतिशत से घटकर 19.2 प्रतिशत रह गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत निरंतर रूप से बढ़ी है (चित्र 6)। सामान्य प्रशासन की बचत में सुधार दिख रहा है, (यद्यपि यह नकारात्मक क्षेत्र में ही बना रहा है), वर्ष 2014-15 तक सरकारी बचत में कमी का

चित्र 6: जीडीपी के हिस्से के रूप में सकल बचत (प्रतिशत)

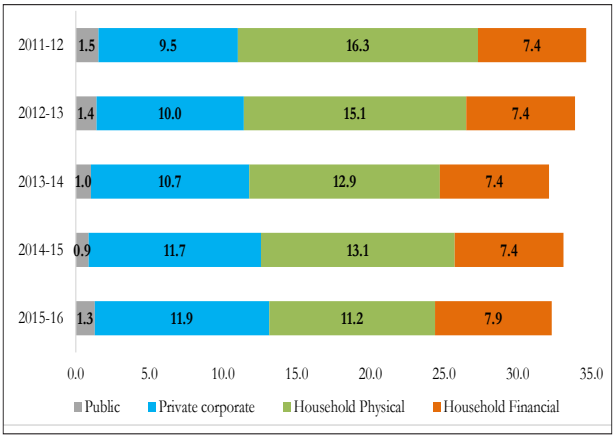

स्रोत: सीएसओ के आंकड़ों पर आधारित।
टिप्पणी: सरकारी क्षेत्र में सामान्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उद्यम शमिल हैं।

कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बचत के निम्न स्तर का होना हो सकता है।

1.19 परिवार क्षेत्र बचत के बड़े परिमाण का हिस्सा रखता है, तथापि, कुल बचत में परिवार बचत का हिस्सा 2011-12 में लगभग 68 प्रतिशत से 2015-16 में 59 प्रतिशत के नजदीक तक गिर गया था। परिवारों की बचत के वर्ग में वास्तविक परिसम्पत्तियों से वित्तीय परिसम्पत्तियों की ओर रूझान हुआ है जिससे कुल घरेलू बचत में वास्तविक परिसम्पतियों का हिस्सा 10 प्रतिशतांक बिन्दुओं से ज्यादा कम हो गया। सरकारी बचत 2011-12 में जीडीपी के 1.5 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 0.9 प्रतिशत रह गई थी जबकि यह 2015-16 में फिर वृद्धि होने लगी है। अंशत: इस की व्याख्या पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि तथा सब्सिडी में कमी द्वारा हो सकती है। जिसमें निजी निगम क्षेत्र का सकल बचत में अंश 2011-12 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में लगभग 12 प्रतिशत पर पहुंच गया।

1.20 वर्ष 2015-16 के बाद के सकल बचत के लिए आंकडा उपलब्ध नहीं है। तथापि, 2016-17 के लिए परिवार क्षेत्र की वित्तीय बचत हेतु प्रारंभिक सूचना भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध है।[2] परिवार द्वारा की गई वित्तीय बचत मुख्य रूप से करेंसी, बैंक जमाएं, जीवन बीमा निधि, भविष्य एवं पेंशन निधि के रूप में तथा कई वर्षों से शेयरों तथा डिबेंचरों के रूप में रखी जाती है। वर्ष 2011-12 और 2015-16 के बीच बैंक खातों में जमाराशि सकल वित्तीय बचत का 50 प्रतिशत थी। वर्ष 2015-16 में बैंक जमा खातों और जीवन बीमा निधियों में वित्तीय बचत किए जाने के अनुपात में पर्याप्त कमी देखी गई तथा मुद्रा, भविष्यनिधि और पेंशन निधियों, सरकार के दावों (मुख्यत: लघु बचत में) के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई। शेयरों और डिबेन्चरों में बचत दोगुना से ज्यादा हो गई तथा शेयरों और डिबेन्चरों के भीतर म्यूचयूल फंड हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में 126% की बढ़ोत्तरी हुई।

1.21 पारिवारिक वित्तीय बचतों का स्वरूप, पिछले 5 वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में पर्याप्त रूप से भिन्न था। जबकि परिवारों की समग्र वित्तीय बचत में वर्ष 2016-17 में 20% से अधिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई (पिछले 5 वर्ष में

[2] सीएसओ जनवरी 2018 के अंत पर वर्ष 2016-17 के लिए अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बचत का अनुमान लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना तथा इसके स्वयं के वास्तविक बचत अनुमानों के आधार पर वित्तीय बचत की सूचना जारी करेगा।

देखी गई बढ़ोतरी से भी अधिक), मुद्रा के रूप में बचत में 250% से अधिक कमी हुई (लगभग 5 लाख करोड़ रु.)। यह कमी मुख्य रूप से नवम्बर 2016 में उच्च मूल्य वाली मुद्रा के नोटों के वापस ले लिए जाने तथा मार्च 2017 के अन्त तक आंशिक पुन: मुद्रीकरण के कारण हुआ। बैंक

चित्र 7: जीडीपी के हिस्से के रूप में पारिवारिक वित्तीय बचत

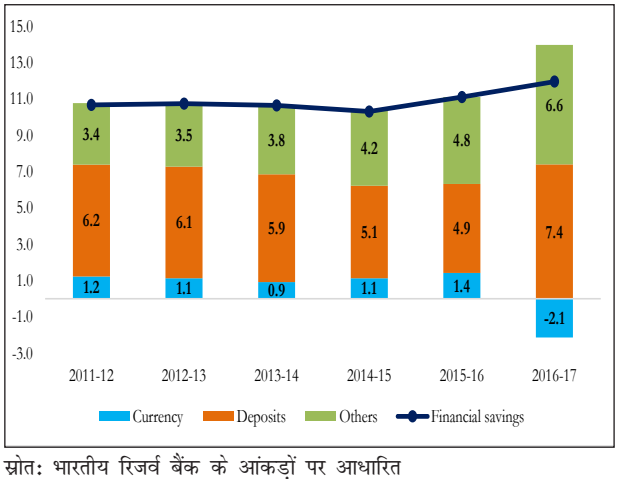

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित
टिप्पणी: सरकारी क्षेत्र में सामान्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उद्यम शमिल हैं।

जमा खातों, जीवन बीमा निधियों और शेयरों तथा डिबेन्चरों में बचत धनराशि 2016-17 में क्रमश: 82%, 66% तथा 345% बढ़ गई (चित्र 7)। शेयरों और डिबेन्चरों की श्रेणी के भीतर, म्यूचुअल फंडों में बचत में, वर्ष 2015-16 की 126% वृद्धि के मुकाबले, 400% से अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। अत: 2 वर्ष के समय में, म्यूचुअल फंड के रूप में बचत में 11 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह उस समय हुआ जब बीएसई सेन्सेक्स लगभग 1.5% प्रति वर्ष की औसत से बढा, जिसको और अधिक विस्तार से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

निवेश

1.22 वर्ष 2015-16, अर्थात वह अद्यतन वर्ष जिसके सम्बन्ध में सकल पूंजीगत निर्माण के बारे में सूचना उपलब्ध है, में निवेश दर में 2011-12 में 39% से 2015-16 में 33.3% तक सतत गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के सम्बन्ध में निवेश के मुख्य घटकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है अर्थात सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जिसमें जीसीएफ का समग्र अनुपात आता है, स्टाक और बहुमूल्य वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन) 2011-12 और 2015-16 के बीच मियादी निवेश दर (जीडीपी के हिस्से के रूप में जीएफसीएफ) में 5% की गिरावट आई। यह 2016-17 में 2 प्रतिशत और गिर गई। वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान यह सुझाते हैं कि यद्यपि स्थिर निवेश की वृद्धि दर 2016-17 में 2.4 प्रतिशत से सुधरकर 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, स्थिर निवेश दर अपने गिरावट के रूझान को बरकरार रखेगी। हाल ही के वर्षों में स्थिर निवेश में धीमी बढ़ोतरी, दोहरे तुलन पत्र के कारण हो सकती है। इस रूझान को यथाशीघ्र वापस लाया जाना है ताकि आने वाले वर्षों में 8% से अधिक की भारी संभवित वृद्धि को हासिल किया जा सके। वर्ष 2011-12 से बहुमूल्य वस्तुओं का हिस्सा सामान्यत: कम होता जा रहा है। तथापि, इसके वर्ष 2016-17 के जीडीपी के 1.1% की तुलना में वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 1.5% होने की संभावना है।

1.23 अर्थव्यवस्था में निवेश के संस्था-वार ब्यौरे में पिछले कुछ वर्ष में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र (जिसमें और सामान्य प्रशासन आते हैं) में निवेश वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक लगातार गिरता रहा। हालांकि यह वर्ष 2015-16 में बढ़कर जीडीपी का 7.5% हो गया। यह वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर दिए गए अधिकतर ध्यान की तर्ज पर है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य प्रशासन द्वारा पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर, (चालू कीमतों पर) वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान औसत 7% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 21% से अधिक हो गयी। कुल निवेश में निजी-कारपोरेट क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2011-12 के 36% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 41% हो गया और यह अब घरेलू क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। पारिवारिक क्षेत्र (परिवारों की सेवा कर रही लाभेतर संस्थाओं सहित) का निवेश 2011-12 में जीडीपी के

चित्र 8: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल निवेश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निवेश (प्रतिशत)

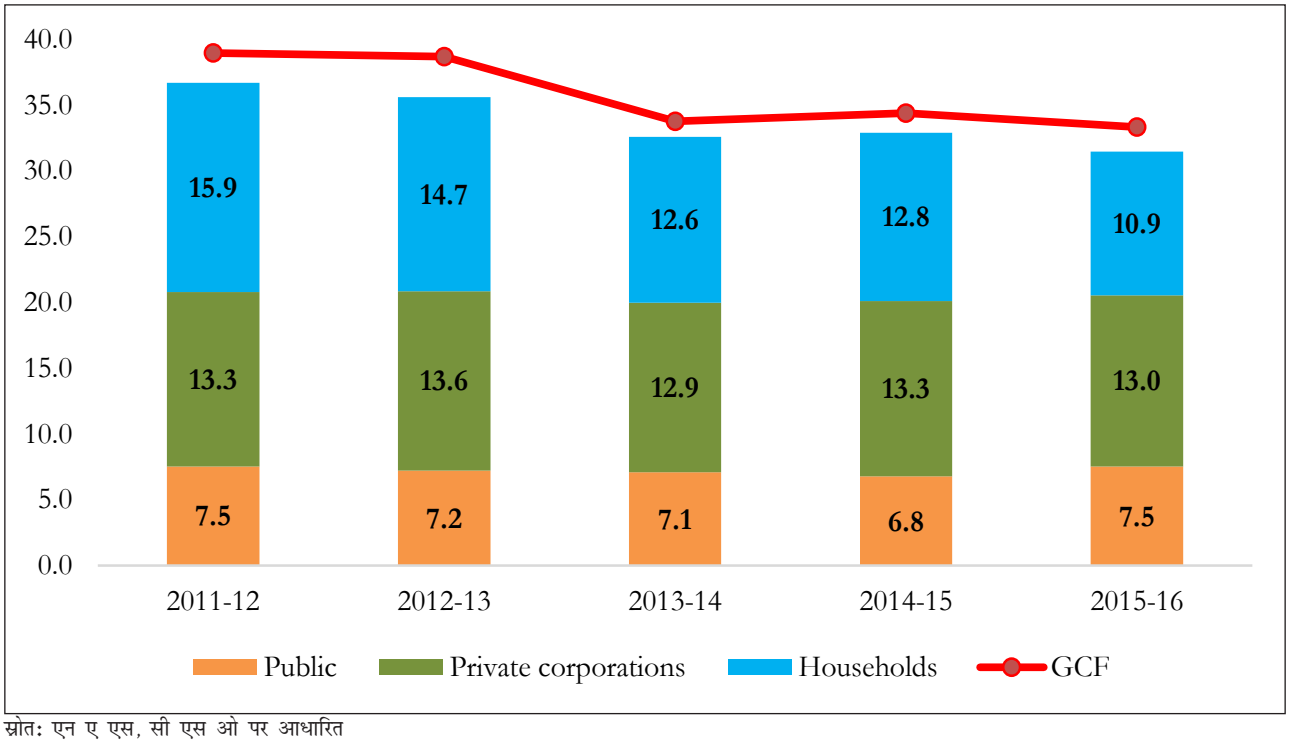

स्रोत: एन ए एस, सी एस ओ पर आधारित

टिप्पणी : विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में कीमती वस्तु और भूल-चूक शामिल नहीं है, इसलिए जीसीएफ तक नहीं शामिल करें

सारणी 4: कुल स्थिर निवेश के हिस्से के रूप में संस्थागत क्षेत्र द्वारा आस्ति-वार स्थिर निवेश आंकडें

		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीएफसीएफ	आवास	57.5	56.6	57.7	58.6	57.1
	मशीनरी और उपकरण	35.0	34.5	31.9	31.6	32.5
	अन्य	7.6	9.0	10.5	9.9	10.5
सरकारी क्षेत्र (सामान्य प्रशासन सहित)	आवास	12.0	12.3	12.7	13.4	16.1
	मशीनरी और उपकरण	8.1	7.3	8.0	7.4	8.1
	अन्य	1.4	1.5	2.0	1.3	1.1
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	आवास	8.0	9.6	9.5	10.0	10.4
	मशीनरी और उपकरण	18.7	18.4	19.6	17.9	18.2
	अन्य	6.0	7.2	8.3	8.3	9.1
परिवार क्षेत्र	आवास	37.4	34.7	35.5	35.2	30.6
	मशीनरी और उपकरण	8.2	8.9	4.3	6.4	6.2
	अन्य	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

स्रोत: एनएएस, सीएसओ।

टिप्पणी : अन्य में आईपीपी और सीबीआर शामिल है।

15.9 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशतांक घटकर 2015-16 में 10.9 प्रतिशत रह गया (चित्र 8)।

1.24 स्थिर निवेश कुल निवेश का लगभग 90 प्रतिशत बैठता है। स्थिर निवेश में उन्नत जैविक संसाधनों (सीबीआर) से प्राप्त होने वाले लघु अंशदान के साथ-साथ आवासों, मशीनरी एवं उपस्कर और बौद्धिक संपदा उत्पादों (आईपीपी) सहित विभिन्न आस्तियां शामिल हैं (सारणी 4)।1.25 आवास पर निवेश स्थिर निवेश का लगभग 57-58 प्रतिशत बैठता है और यह हिस्सा 2011-12 तथा 2015-16 के बीच उचित रूप से स्थिर बना हुआ है। तथापि, आवासों में परिवारों का निवेश काफी घट गया है, जिसका संभावित कारण भौतिक आस्तियों के रूप में परिवारों की बचत के हिस्से में ह्रास होना है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थिर निवेश में प्राय: समस्त बढ़त आवासों में है। स्थिर निवेश के मशीनरी खंड के हिस्से में ह्रास ही परिवार क्षेत्र में अधिकांश ह्रास का कारण है। 'अन्य' (सीबीआर के साथ-साथ आईपीपी) का हिस्सा निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा इस श्रेणी में उच्च निवेश करने के कारण बढ़ गया।

लोक वित्त

1.26 अधिकांश राजकोषीय संकेतकों जैसे-राजस्व उत्प्लावन, व्यय गुणवत्ता, कर अंतरण एवं घाटा-में प्रत्यक्ष सुधारों द्वारा प्राप्त दृढ़ आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने राज्यों की साझेदारी से, चिरप्रतीक्षित वस्तु और सेवाकर जीएसटी व्यवस्था को जुलाई, 2017 से प्रारंभ किया। जीएसटी का प्रवर्तन व्यापक तैयारियों एवं बहुस्तरीय परामर्श के बाद किया गया, तथापि, इस पूर्णतया परिमाणपरक परिवर्तन का अभिप्राय यह था कि आगामी अनिश्चितता और संभावित लागतों का प्रबंध सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है। सरकार इस संभावना कि अंतिम माह (मार्च, 2018) के जीएसटी संग्रहणों का पर्याप्त भाग अगले वर्ष में जमा हो सकता है, के साथ परिवर्तन एवं चुनौतियों के संबंध में मार्गदर्शन कर रही है।

1.27 केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों के आंकड़े महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से नवंबर 2017 तक उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, राजस्व मोर्चे पर, चालू वर्ष के प्रथम आठ माह में तीन विशिष्ट प्रवृत्तियाँ देखी गईं: प्रत्यक्ष कर संग्रहण उचित रूप से पटरी पर है; कर-भिन्न राजस्व का निष्पादन अल्प रहा है, और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां, मुख्यत: विनिवेश से आय, सही दिशा में है।

1.28 केंद्र के प्रत्यक्ष कर[3] संग्रहण में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष जैसी ही रही। पूर्ण वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अप्रत्यक्ष करों में बजट विहित वृद्धि मात्र 7.6 प्रतिशत है; नवंबर तक यह वास्तविक वृद्धि 18.3 प्रतिशत है। इस वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष करों में अंतिम प्राप्ति केंद्र-राज्यों के बीच जीएसटी लेखों के अंतिम निपटान पर निर्भर करेगी और यह सम्भावना है कि ग्यारह महीनों में केवल करों (आयात पर आईजीएसटी को छोड़कर) की वसूली की जाएगी। 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान राज्यों का कर-हिस्सा लगभग 25.2 प्रतिशत बढ़ा, जो केन्द्र के निवल कर राजस्व में हुई 12.6 प्रतिशत वृद्धि तथा सकल कर राजस्व में हुई 16.5 प्रतिशत वृद्धि से बहुत अधिक है।

1.29 वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सरकार का कुल व्यय 14.9 प्रतिशत बढ़ा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 12.6 प्रतिशत था। चालू वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय 13.1 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 29.3 प्रतिशत तक बढ़ गया। बजट चक्र और इसकी प्रक्रिया को लगभग एक महीने आगे बढ़ाने से व्ययकर्त्ता एजेंसियों को वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से योजना बनाने और कार्यान्वयन को शीघ्र शुरू करने का व्यापक अवसर मिल गया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय व्यय में तीव्र गति से प्रगति हुई। कुछ व्ययों के आगे जुड़ने और बढ़े हुए ब्याज व्यय के साथ इसने राजकोषीय घाटे पर और दवाब डाला जो नवम्बर, 2017 तक बजट अनुमान के 112 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा यह वृद्धि कुछ हद तक सामान्य हो जाएगी।

1.30 विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों के राजकोषीय सन्तुलन में 'उदय' यूडीएवाई-उत्प्रेरित असामान्य कमी के पश्चात राज्यों ने वर्तमान वर्ष में सुदृढ़ता हासिल करने का लक्ष्य रखा। 21 राज्यों की सरकारों की स्थिति जो कुल जीएसडीपी के लगभग 86 प्रतिशत के बराबर है और जिसके लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं, यह प्रदर्शित करती है कि उनकी राजस्व प्राप्तियों ने वृद्धि की दृष्टि से और तदनुरूप बजट अनुमानों के संबंध में विगत वर्षों के साथ तालमेल दर्शाया है। यदि नवम्बर 2017 तक के

---

[3] प्रत्यक्ष कर में वैयक्तिक आय कर एवं कारपोरेट कर शामिल है।

संकेतक बरकरार रहते हैं तो मौजूदा वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सभी राज्य मिलकर एक साथ मिलकर राज्यों के पहुँच के भीतर हो सकता है।

1.31 जीएसटी से प्रत्याशित राजस्व के और अधिक स्पष्ट हो जाने के साथ, बजट अनुमान की तुलना में केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय संतुलन चौथी तिमाही में राजस्व व्यय की उभरती प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगा।

कीमतें और मौद्रिक प्रबंधन

कीमतें एवं मुद्रास्फीति

1.32 वर्ष 2017-18 के दौरान देश में मुद्रास्फीति धीमी बनी रही। उपभोक्ता कीमत सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 की इसी अवधि की 4.8 प्रतिशत की दर से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में 3.3 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में खाद्य पदार्थों की निम्न महंगाई दर के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति 3.0 प्रतिशत से कम रही, विशेषकर दालों और सब्जियों की महंगाई में मामूली वृद्धि हुई और यह वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 3.0 प्रतिशत रही। उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक (सीएफपीआई) के संबंध में खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 5.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 1.2 प्रतिशत रह गई। सीपीआई-आधारित मुख्य (खाद्य-भिन्न, ईंधन-भिन्न) मुद्रास्फीति भी वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.5 प्रतिशत रह गई। आवास तथा ईंधन एवं प्रकाश समूहों को छोड़कर, सीपीआई-सी के सभी मुख्य उप समूहों की मुद्रास्फीति में वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में गिरावट आई। खाद्य और पेय पदार्थों में इस गिरावट की दर सबसे तेज रही।

1.33 थोक कीमत सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) पर आधारित औसत मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसम्बर) में 0.7 की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.9 प्रतिशत रही। कई महीनों तक मंद रहने के बाद डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य में आई अचानक तेजी के कारण फरवरी और मार्च, 2017 के दौरान बढ़ गई। इसके पश्चात्, विश्व में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट आने के साथ जून 2017 में 0.9 प्रतिशत के निम्न स्तर तक पहुंचते हुए मुद्रास्फीति भी जुलाई तक अगले चार महीनों के दौरान सामान्य रही। बाद के महीनों में कच्चे तेल की कीमत में पुनः उछाल आने और इसके बढ़ते जाने तथा बढ़ती खाद्य कीमतों के साथ दिसम्बर, 2017 में मुद्रास्फीति भी बढ़ी और 3.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

1.34 डब्ल्यूपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 की अवधि की 6.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.3 प्रतिशत रह गई। डब्ल्यूपीआई, ईंधन एवं विद्युत मुद्रास्फीति पूर्व वर्ष की (-)6.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुख्य स्फीति (गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों) बढ़कर वर्ष 2016-17 (अप्रैल-नवम्बर) के 1.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.6 प्रतिशत रही। तथापि, डब्ल्यूपीआई के सम्पूर्ण वर्ग (बास्केट) में 64.2 प्रतिशत का भार रखने वाली विनिर्मित पदार्थ स्फीति 2.6 प्रतिशत के आस-पास बनी रही।

मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय हस्तक्षेप

1.35 वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधित सांविधिक ढांचे के अंतर्गत मौद्रिक नीति का संचालन किया गया जो 5 अगस्त, 2016 से प्रभावी हुई। वर्ष 2017-18 के लिए तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण (अगस्त, 2017) में मौद्रिक नीति समिति ने 6.0 प्रतिशत नीतिगत रेपोरेट के 25 आधार बिन्दु तक घटाने का निर्णय लिया। इसने अक्तूबर और दिसम्बर, 2017 दोनों माह में इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया।

1.36 पुनःमौद्रिकरण प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाते हुए, 17 नवम्बर, 2017 से एक अनुकूल आधार प्रभाव निर्धारित करने के साथ, प्रचलन मुद्रा और आरक्षित मुद्रा (एमओ) दोनों की वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि तीव्र रूप से सकारात्मक बनी रही और पिछले वर्ष की अपनी संबंधित वृद्धि दरों से उच्च रही। नवम्बर, 2016 की शुरूआत में विमुद्रीकरण के पश्चात, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक, दोनों विलेखों का मिश्रित रूप से उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक ने अपने नकदी समावेशन कार्यों को गति प्रदान की। नकदी की स्थिति आधिक्य की अवस्था में बनी रही।

उत्तरोतर पुनर्पूंजीकरण के साथ इसका प्रभाव धीरे-धीरे सामान्य होता गया।

1.37 बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, के कार्य निष्पादन में चालू वित्तीय वर्ष में नरमी बनी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादनकारी अग्रिम (जीएनपीए) मार्च 2017 और सितम्बर, 2017 के बीच 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया। नवम्बर, 2016 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में खाद्य-भिन्न क्रेडिट (एनएफसी) नवम्बर, 2017 में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया। सेवाओं और निजी ऋण खंड को बैंक ऋण का उधार, समग्र एनएफसी वृद्धि के लिए प्रमुख योगदानकर्त्ता बना रहा।

विदेशी क्षेत्र

1.38 वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है और वर्ष 2016 में यह 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व व्यापार का परिमाण वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2018 में 4.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्षों की गिरावट के विपरीत वस्तुओं की कीमत (ईंधन और ईंधन भिन्न) भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब तक, भारत का विदेशी क्षेत्र वर्ष 2017-18 में लोचशील और सुदृढ़ बना रहा है तथा जीडीपी के 1.8 प्रतिशत पर चालू खाता घाटा (सीएडी), वाणिज्यिक निर्यात में 12 प्रतिशत की वृद्धि, निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि, निवल विदेशी निवेश में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2017-18 में एच1 में बेहतर विदेशी ऋण संकेतकों के साथ भुगतान शेष (बीओपी) की स्थिति संतोषप्रद बनी हुई है।

भारत का वाणिज्यिक व्यापार

1.39 नकारात्मक वृद्धि के दो वर्षों के पश्चात वर्ष 2016-17 को वाणिज्यिक निर्यात में सकारात्मक वृद्धि वाले वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। इसी प्रकार नकारात्मक वृद्धि के तीन वर्षों के पश्चात् वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक आयात में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में निर्यात 491 बिलियन अमरीकी डालर से लगभग 107 बिलियन अमरीकी डालर घटकर वर्ष 2016-17 में 384 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। मुख्य रूप से यह गिरावट 77 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में कमी तथा इस अवधि के दौरान सोने और चांदी के आयात में 26.4 बिलियन अमरीकी डालर तक कमी के कारण आई। इस प्रकार लगभग इन दो सामग्रियों के समूह के कारण ही आयात में 97 प्रतिशत की कमी आई। आयात में सामग्री में गिरावट को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से आई गिरावट के कारण माना जा सकता है। कच्चे तेल के भारतीय समूह की आयात कीमत वर्ष 2012-13 में 108 अमरीकी डालर प्रति बैरल के औसत से गिरकर वर्ष 2016-17 में 47.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल रह गयी। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी आने से पीओएल निर्यातों की कीमत में भी कमी आ गई, जो 2012-13 में लगभग 61 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2016-17 में 32 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गई। पीओएल-भिन्न निर्यात 2012-13 में 239.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2016-17 में 244.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। इन वर्षों में कुल व्यापारिक निर्यातों में लगभग 24.5 बिलियन अमरीकी डालर तक की गिरावट आई।

1.40 निर्यातों की कीमत के मुकाबले आयातों की कीमत में आई अधिक कमी व्यापारिक कारोबार के संतुलन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार रही, जो 2012-13 में 190 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2016-17 में 108.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गई (चित्र 9)। इस अवधि में व्यापार घाटे में कमी ने चालू खाता घाटे की स्थिति में कुछ सुधार लाने में काफी योगदान दिया, जो 2012-13 में जीडीपी के 4.8 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत रह गया। पूंजी प्रवाह अच्छे स्तरों पर बने रहने से, विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2013 के अंत में 292 बिलियन अमरीकी डालर से तेजी से बढ़कर मार्च 2017 के अंत में 370 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

1.41 2016-17 की पहली छमाही में भारत की निर्यात वृद्धि (-) 1.3 प्रतिशत पर नकारात्मक बनी रही। तथापि, 2016-17 की दूसरी छमाही में, इसमें सुधार आना शुरू हुआ और वर्ष 2016-17 में इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात वृद्धि में और तेजी आई और यह 12.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारत की

निर्यात परिमाण वृद्धि, जो मार्च 2016 से सकारात्मक हो गई थी, में अप्रैल 2017 तक उछाल आया, परंतु इसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। यद्यपि यह अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में, आयातों में 21.8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। मुख्यतया कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पीओएल आयात वृद्धि 24.2 प्रतिशत थी और स्वर्ण

भुगतान शेष:

1.42 भारत की भुगतान शेष की स्थिति, जोकि वर्ष 2013-14 से सुसाध्य रही है, प्रथम छमाही में सीएडी में कुछ वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही तक वैसी ही बनी रही है। 18 (अप्रैल-दिसंबर) व्यापार घाटा 114.9 बिलियन तक बढ़ गया। भारत का सीएडी में

चित्र 9. निर्यात, आयात और व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)

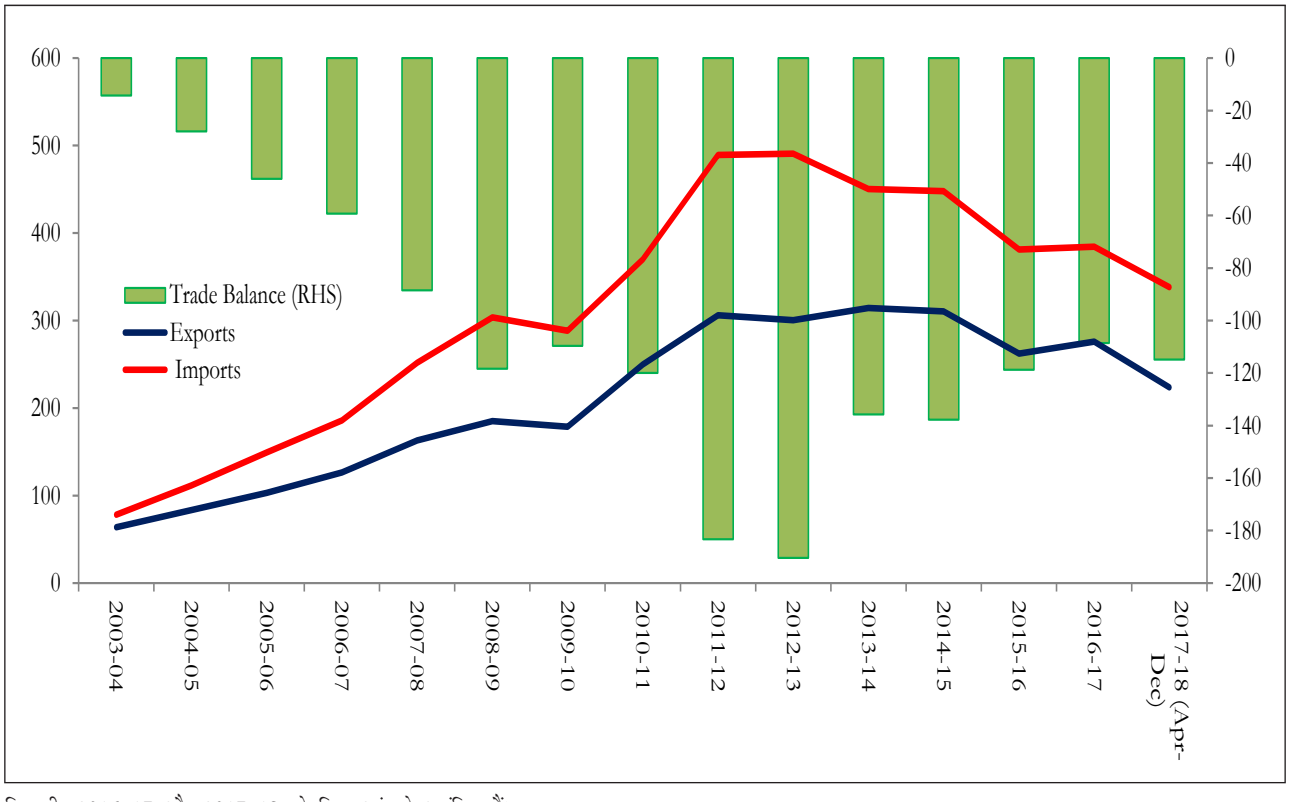

टिप्पणी: 2016-17 और 2017-18 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

तथा चांदी आयातों में 52 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पीओएल-भिन्न आयातों में 22.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पीओएल-भिन्न और स्वर्ण-भिन्न और चांदी आयात 18.1 प्रतिशत तक बढ़ गए। भारत का व्यापार घाटा, जिसमें वर्ष 2014-15 और 2016-17 से लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, वर्ष 2016-17 में पहली छमाही में 43.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 74.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसम्बर) में, व्यापार घाटा 114.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया।

वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 3.9 बिलियन अमेकिी डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत, था जो वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में 22.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया (सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत), जिसका प्रमुख कारण निर्यातों के संगत मर्केंडाइज आयातों में अधिक वृद्धि थी जो उच्च व्यापार घाटा है। सोने के आयात में हुई तीव्र वृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल कीमतों में हुई वृद्धि के कारण आयातों में उछाल आया है। वर्ष 2016-17 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई

है जिसका कारण 'अदृश्य' बैलेंस में सुधार के साथ-साथ विदेशी निवेश द्वारा निवल पूंजी प्रवाह की अधिकता थी और साथ ही बैंकिंग पूंजी व्यापार घाटे को वित्त प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी जिससे वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रामाणिक वृद्धि दिखाई थी।

अदृश्य घटक

1.43 वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों में वृद्धि के कारण निवल अदृश्य अतिरेक में 52.5 विलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जबकि वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में यह 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही के दौरान वर्ष-दर वर्ष आधार पर निवल सेवा प्राप्तियों में मुख्यत: यात्रा और दूरसंचार तथा कंप्यूटर और सूचना सेवाओं से हुई निवल आय में वृद्धि होने से 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में निजी अंतरण प्राप्तियां, मुख्यत: विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित धन, पूर्व वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखा रही है। निवल निवेश आय के संबंध में होने वाला बर्हिगमन जो पिछले दो वर्षो में लगातार बढ़ रहा था उसमें 2017-18 की पहली छमाही में वृद्धि बरकरार रही और वह 2016-17 की पहली छमाही में 14.9 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 15.3 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया।

वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बीओपी का पूंजी/वित्त खाता

1.44 वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंत:प्रवाह में गिरावट के होते हुए भी भारत के पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि के चलते निवल विदेशी निवेश में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में एफडीआई प्रवाह में मंदी के कारण पूर्व वर्ष की संगत अवधि के दौरान इसके स्तर में वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में 7.3 प्रतिशत की समेकित गिरावट आई है। तथापि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुई थी जिसमें 78.0 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के साथ वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बढ़कर 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के बारे में एक सकारात्मक संकेत है।

विदेशी मुद्रा भंडार

1.45 दिसंबर 29, 2017 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वाधिक उच्चस्तर के साथ 409.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दिसंबर 2016 के अंत से वर्ष-दर वर्ष आधार पर यह वृद्धि 14.7 प्रतिशत थी जबकि मार्च 2017 के अंत से दिसंबर 2017 के अंत में यह वृद्धि 10.6 प्रतिशत (370.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गई। सामान्य शब्दों में विदेशी मुद्रा भंडार में (मूल्य निर्धारण प्रभावों सहित) वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान 30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्त्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। नवंबर 2017 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर में 12.2 महीनें हो गया जबकि मार्च 2017 के अंत में यह 11.3 महीने थी।

विनिमय दर

1.46 वर्ष 2017-18 के दौरान (दिसंबर 2017 तक) अमेरिकी डालर की तुलना में सामान्यत: रुपए का कारोबार वृद्धिमान दर पर हुआ हालांकि सितंबर 2017 में कुछ-कुछ गिरावट भी दर्ज की गई थीं। दिसंबर 2017 के दौरान 64. 24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचने से रुपए में 2.6 प्रतिशत की मजबूती आई जबकि मार्च 2017 के दौरान एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 65.88 रुपए थी जिसका कारण अत्यधिक पूंजी प्रवाह था। अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिमूल्यन की प्रवृत्ति जनवरी में जारी रही है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, औसत आधार पर, अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ अन्य मुख्य मुद्राओं के मुकाबले में भी रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है। औसतन रूप से (अप्रैल-दिसंबर, 2017 में) अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त अन्य मुख्य मुद्राओं के मुकाबले भी रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है। रुपए के मूल्य में वृद्धि होना (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर आरईईआर के संदर्भ में) यह दर्शाता है कि भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है।

1.47 पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिकी डॉलर की तुलना में

बॉक्स. 1.2: अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए की स्थिरता

हाल के वर्षों में, बाह्य सेक्टर में हुए विकास की मुख्य विशेषता रुपए और डॉलर के बिलियम दर की स्थिरता और उस वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की दर में कमी रही है। 2011-12 और 2013-14 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में 21 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ था, जबकि 2014-15 और 2016-17 के बीच इसमें 8.8 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ है। 2016-17 के बाद 2017-18 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में औसतन मूल्य में वृद्धि हुई है। वार्षिक औसत दर से औसत दैनिक रुपए-डॉलर के विनिमय दर में होने वाले घट-बढ़ के संबंध में उस वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की माप की गई है। और उस वार्षिक औसत के घटबढ़ के गुणांक के द्वारा इसे दर्शाया गया है। पिछले चार वर्षों में (2014-15 से 2017-18 (दिसंबर के अंत तक) घटबढ़ का गुणांक बहुत कम रहा है जो एक अधिक स्थिर वर्ष के दौरान (कम घटबढ़) रुपए-डॉलर विनिमय दर को दर्शाता है।

सारणी 1 : रुपए-डॉलर विनिमय दर

	रुपयए/डॉलर विनिमय दर (वर्ष का औसत)	मानक घट-बढ़	घट-बढ़ का गुणांक (प्रतिशत)
2011-12	**47.92**	**3.03**	**6.32**
2012-13	**54.41**	**1.25**	**2.29**
2013-14	**60.50**	**3.06**	**5.05**
2014-15	**61.14**	**1.19**	**1.94**
2015-16	**65.46**	**1.69**	**2.57**
2016-17	**67.07**	**0.71**	**1.06**
2017-18 (दिसंबर की समायित तक)	**64.49**	**0.42**	**0.65**

स्रोत: आर.बी.आई. से उपलब्ध दैनिक विनिमय दर से प्राक्कलित

रुपए का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। 2014-15 और 2016-17 की तुलना में 2011-12 और 2013-14 के बीच मूल्यह्रास का स्तर बहुत अधिक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ष उतार-चढ़ाव की दर में भी कमी आई है (बॉक्स 1.2 देखें)।

विदेशी कर्ज

1.48 मार्च 2017 के अंत से सितंबर, 2017 के अंत तक भारत के विदेशी कर्ज के स्टॉक में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे यह कर्ज बढ़कर 495.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋण में शामिल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ जाने के कारण दीर्घावधि के ऋण में वृद्धि हुई है। मुख्यत: व्यापार से संबंधित क्रेडिटों में हुई वृद्धि के कारण अल्पावधि के ऋण में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यत: सरकार के अन्य विदेशी कर्ज के अंश के कारण मूल ऋण में सरकार के हिस्से का ऋण जो मार्च, 2017 की समाप्ति में 19.4 प्रतिशत थी, वह सिंतबर 2017 तक बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गई है जो सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी विशेष निवेश के बढ़ते स्तर को दर्शाया है। विदेशी कर्ज को मार्च 2017 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का 78.4 प्रतिशत था, वह सितंबर 2017 में बढ़कर 80.7 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के वास्तविक परिपक्वता के द्वारा अल्पावधि के ऋण का अनुपात जो मार्च 2017 के अंत में 23.8 प्रतिशत था वह सितंबर 2017 के अंत में घटकर 29.2 प्रतिशत हो गया है।

व्यापार नीति

1.49 वर्ष के दौरान व्यापार नीति में होने वाले दो महत्वपूर्ण सुधार हैं, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा तथा दिसंबर, 2017 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की हालिया बहुपक्षीय वार्ता। व्यापार संभारिकी के मोर्चे पर तथा डंपिंग-रोधी उपायों के संबंध में कुछ प्रगति हुई है। अधिसूचित सेवाओं हेतु टेक्स्टाइल क्षेत्र के दो उप-सेक्टरों के लिए एमईआईएस (मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम) और एसईआईएस (सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम प्रोत्साइनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके साथ-साथ दिसंबर, 2017 में सरकार द्वारा लेदर एवं फुटवियर सेक्टर में रोजगार निर्माण हेतु एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया गया है, जिससे इन सेक्टरों से होने वाले निर्यातों में मदद मिलने की संभावना है।

भारतीय संभारिकी (लॉजिस्टिक) बाजार के वर्ष 2019-20 में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते हुए निर्यातों पर संवर्धित संभारिकी का व्यापक प्रभाव है। सरकार ने संभारिकी क्षेत्र के एकीकृत विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

वर्ष 2018-19 के लिए विकास की भावी संभावनाएं:

1.50 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) का प्राक्कलन है कि वर्ष 2017-18 में जीडीपी विकास की दर 6.5 प्रतिशत पर रहेगी। हालांकि, कुछ ऐसे संकेतक हैं जो विगत कुछ दिनों के दौरान सामने आए है जैसे विनिर्माण सेवाएं पीएमआई, औद्योगिक क्षेत्र का विकास जैसाकि उच्चतर आईआईपी द्वारा परिलक्षित हुआ है, ऑटोमोबाइल विक्रय, इत्यादि, जिनसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी विकास दर सीएसओ के प्राक्कलन की तुलना में थोड़ा-सा अधिक हो सकती है (यह 6.5 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत के बीच रह सकती है)। वर्ष 2018-19 के लिए संवृद्धि में अनेक कारकों के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। सकारात्मक पक्ष पर, अक्टूबर 2017 में विमोचित आईएमएफ के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018 में 3.7 प्रतिशत पर आने की उम्मीद है। इससे भारत के निर्यातों में अतिरिक्त तेजी आने की संभावना है जिसने चालू वर्ष में तेजी को पहले की दर्शा दिया है। धनप्रेषणों, जिन्होंने चालू वर्ष की प्रथम छमाही में पुन: प्रवर्तन का संकेत दिया है, में तेजी आने की आशा की जा सकती है, विशेष रूप से यदि तेल की कीमतें चालू वर्ष के अनुरूप ही बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती रहें।

1.51 देश में निवेश गतिविधि के पुन:प्रवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और स्थिर निवेश की वृद्धि में हालिया उछाल के आगामी वर्ष में यही गति बनाए रखने की अपेक्षा की जा सकती है। यदि महंगाई दर अपने मौजूदा स्तरों से अधिक ऊपर नीचे नहीं होती है तो नीतिगत दरों के पूरी तरह स्थिर बने रहने की आशा की जा सकती है। यह, वैश्विक बाजारों में प्रचलित अभी तक अनुकूल ब्याज दर व्यवस्था के साथ निवेश के वातावरण को और अधिक निश्चितता प्रदान कर सकती हैं। वर्ष 2017-18 में किए गए सुधारात्मक उपायों के वर्ष 2018-19 में भी और सुदृढ़ होने और विकास की गति को बल देने की अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी ओर, उच्च वृद्धि को होने वाले अधोवर्ती जोखिम उच्चतर कच्चे तेल की कीमत से होते हैं, जिनके (वर्तमान संकेतों के अनुसार), वर्ष 2017-18 के लिए लगाया 56-57 अमेरिकी डालर प्रति बैरल (भारतीय बाजार के लिए) के संभावित औसत के ऊपर अधिक से अधिक लगभग 10-15 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। कुछ देशों में संरक्षण ावादी नीतियां निर्यात-वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं जबकि विकसित देशों में मौद्रिक शर्तों को कड़ा करने की संभाव्यता से पूंजी के अंत:प्रवाहों में कमी आ सकती है। इस मौद्रिक कठोरता से वित्तीय संकट की संभावना भी हो सकती है और अधोवर्ती जोखिम हो सकता है। इसके समाध ान पर वर्ष 2018-19 में संवृद्धि दर के उच्चतर रहने की मजबूत संभावना है और यह वर्ष 7.0 से 7.5 प्रतिशत के बीच में जीडीपी संवृद्धि दर पर समाप्त होने की संभावना है।

क्षेत्रवार घटनाक्रम

कृषि एवं सहायक सेक्टर

1.52 आम तौर पर अन्य बातों के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया में जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट आती है, जोकि भारत में भी देखा जा रहा है। जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 17.4 प्रतिशत हो गया (वर्तमान कीमतों पर)। हालांकि हिस्सेदारी में गिरावट रोजगार, जीविका और खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र के महत्व को नकारता नहीं है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र स्वयं भी हाल के वर्षों में क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। कृषि के जीवीए में पशुधन की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 से लगातार बढ़ रही है जबकि फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 65 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 60 प्रतिशत हो गई है।

1.53 कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए चतुर्थ अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार भारत ने वर्ष 2016-17 के दौरान खाद्यान्न का लगभग 275.7 मिलियन टन रिकार्ड उत्पादन किया। वर्ष 2017 के खरीफ सीजन के दौरान अधिकांश फसलों का अनुमानित उत्पादन पिछले पांच वर्षों के उनके सामान्य उत्पादन की तुलना में अधिक रहने का अनुमान लगाया है। 22 सितंबर, 2017 को रिलीज किए गए प्रथम अग्रिम प्राक्कलन (एई) के

सारणी 5: कृषि क्षेत्र-प्रमुख संकेतक

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (PE)	2017-18 (AE)
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए वृद्धि (2011-12 में वर्तमान कीमतों पर)	1.5	5.6	-0.2	0.7	4.9	2.1
कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा (वर्तमान कीमतों पर)	18.2	18.6	18.0	17.5	17.4	16.4
कुल जीसीएफ में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा, जिसमें से	7.7	9.0	8.3	7.8	na	na
फसल की हिस्सेदारी'	6.5	7.7	6.9	6.5	na	na
पशुधन की हिस्सेदारी'	0.8	0.9	0.8	0.8	na	na
वानिकी और लट्ठे बनाना क्षेत्र*	0.1	0.1	0.1	0.1	na	na
मछली पालन का हिस्सा *	0.4	0.5	0.5	0.5	na	na

नोट*: कुल जीसीएफ में हिस्सेदारी, जोकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2017 तथा वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुमानों पर आधारित हैं। एनए: उपलब्ध नहीं
स्रोत: केंद्रीय सांख्यकी कार्यालय

अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न का उत्पादन 134.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जोकि वर्ष 2016-17 की तुलना में 3.9 मिलियन टन कम था। वर्ष 2017-18 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 94.5 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 96.4 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 2017-18 के दौरान दलहन का कुल उत्पादन 8.7 मिलियन टन, गन्ने का 337.7 मिलियन टन, तिलहन का 20.7 मिलियन टन और कपास का 170 किलो ग्राम के 32.3 मिलियन गांठों का अनुमान है।

1.54 यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे-2017 के मुताबिक भारत विश्व में निवल फसली क्षेत्र (179.8 एमएचए) के 9.6 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। अत: भारत में विविध फसल उगाने और कृषि को एक टिकाऊ एवं लाभदायक आर्थिक गतिविधि बनाने की जबर्दस्त क्षमता है। हालांकि फसलों का पैटर्न विभिन्न कारकों, जैसे कृषि जलवायु, जोत का आकार, कीमतें, लाभप्रदता और सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार एक अत्यधिक विविधीकृत फसल पैटर्न को प्राप्त करने के लिए मूल हरित क्रांति वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल विविध करण कार्यक्रम को लागू कर रही है ताकि धान के क्षेत्रों का सदुपयोग करते हुए वहां जल की कम आवश्यकता वाली फसलें उगाई जा सकें। यह किसानों को लगने वाले कीमत संबंधी झटकों और उत्पादन/फसल हानियों के जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

1.55 कृषि उत्पादकता महत्वपूर्ण इनपुट जैसे सिंचाई, बीज, खाद, क्रेडिट, मशीन, प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के उपयुक्त प्रयोग से निर्धारित की जाती है। इनपुट सर्वे (2011-12) के अनुसार कुल परिचालित जोत में से केवल 9.4 प्रतिशत प्रमाणित बीजों का उपयोग करते हैं, 27.0 प्रतिशत अधिसूचित किस्मों के बीज का उपयोग करते हैं और केवल 9.8 प्रतिशत हाइब्रिड (संकर) बीजों का उपयोग करते हैं। कुल फसली क्षेत्र निवल सिंचित क्षेत्र का अखिल भारतीय प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 34.5 प्रतिशत था जो वर्षा जल पर निर्भर भारत में कृषि का बड़ा हिस्सा बनाता है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सिंचाई क्षेत्र की कवरेज और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रीति से 76.0 लाख हैक्टेयर को शामिल करते हुए 99 मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कमान एरिया विकास की सहायता से मिशन तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

1.56 एनएसएसओ रिपोर्ट (जुलाई 2012-जून 2013) से संकेत प्राप्त हुआ है कि फसल उत्पादन से संबंधित क्रियाकलापों में कार्यरत परिवारों का बहुत ही छोटा हिस्सा अपनी फसलों का बीमा करवाता था। कृषि संबंधित कामकाज में लगे हुए परिवारों को फसल बीमा के बारे

में जागरूक करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जो उपज सूचकांक आधारित बीमा योजना है, और 2016 में शुरू की गई थी, पूर्व की स्कीमों की तुलना में अधिक भूमि को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। खरीफ़ 2016 के मौसम के दौरान 23 राज्यों ने पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया और 2016-17 के रबी के मौसम के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया। दिसंबर, 2017 को यथास्थिति, पीएमएफबीवाई, 116 लाख किसानों (आवेदनों) के लिए कुल 13292 करोड़ रुपए के दावे अनुमोदित किए गए हैं और 12020 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है।

उद्योग, कारपोरेट और अवसंरचना निष्पादन

1.57 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), जोकि आधार वर्ष 2011-12 के साथ एक परिमाणात्मक सूचकांक है, दर्शाता है कि औद्योगिक उत्पाद में, अप्रैल-नवंबर, 2017-18 के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 3.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की जर्बदस्त वृद्धि तथा खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत की संयत वृद्धि का समग्र प्रभाव है। आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों, यानी, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर्स, इस्पात, सीमेंट और बिजली, जिनका आईआईपी में कुल लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है, में अप्रैल-नवंबर, 2017-18 के दौरान 3.9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि धनात्मक रही। इस्पात उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि कच्चे तेल और फर्टिलाइजर उत्पादन में उक्त अवधि के दौरान सीमांत गिरावट हुई। नवंबर, 2017 में आईआईपी ने 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान अप्रैल से नवंबर में यह वृद्धि 3.2 प्रतिशत थीं।

1.58 भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवंबर, 2017 के अंत में उद्योगों में नामिक बकाया क्रेडिट वृद्धि में नवम्बर, 2016 के अंत तक हुई वृद्धि की तुलना में 1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। ऋण क्षेत्र की मंदी के संदर्भ में भारतीय फर्मों द्वारा की गई निधियों की मांग को कुछ हद तक वैकल्पिक स्रोतों, जैसे कि कारपोरेट बांड, विदेशी वाणिज्यिक उधारियां और वाणिज्यिक प्रपत्र इत्यादि द्वारा पूरा किया गया है।

1.59 विश्व बैंक की अद्यतन ''डूइंग बिजनेस रिपोर्ट-2018'' में भारत ने अपनी पूर्ववर्ती 130 रैंक से 30 पायदान की छलांग लगाई है। मूडी इंवेस्टर्स सर्विस ने भी भारत की रेटिंग को नीचे से उठाते हुए Baa 3 से Baa 2 के ग्रेड में रेटिंग की है। यह सब माल और सेवा कर, शोधन अक्षमता और दिवालियापन कोड और बैंक पुनर्पूंजीकरण की घोषणा के कार्यान्वयन को शामिल करते हुए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण हुआ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्टार्ट-अप इंडिया और बौद्धिक अधिकार नीति सहित औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं।

1.60 क्षेत्रवार की गई पहल

- **इस्पातः** चीन, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से किए जाने वाले सस्ते स्टील के आयात की डंपिंग की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने सीमाशुल्क में वृद्धि की है और एंटी-डंपिंग शुल्क अधिरोपित किया है। इसी प्रकार, एक वर्ष की अवधि के लिए, फरवरी, 2016 में कुछ मदों पर न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) शुरू की। इन उपायों से घरेलू उत्पादकों को मदद मिली और निर्यातों में वृद्धि हुई। फरवरी 2017 में सरकार ने विविध स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क और प्रतिकारी शुल्कों की अधिसूचना जारी की। सरकार ने मई 2017 में एक नई इस्पात नीति की शुरूआत की।

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रः** एमएसएमई सेक्टर की बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर प्रदान करने में और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म औद्योगिक यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के लिए पुनः वित्तीयन करने और उनका विकास करने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की लागू की है।

- **वस्त्र और परिधानरू** परिधान फर्मों के सम्मुख आई कुछ समस्याओं के निव.

ारण के लिए, कैबिनेट ने जून, 2016 को परिधान सेक्टर के लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसमें यह पाया गया था कि जून 2016 में इसके लागू होने से, पैकेज का मानव निर्मित धागों (फाइबर) से बने रेडीमेड गारमेंटस (आरएमजी) के निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था जबकि इसका ऊन के सिवाय अन्य प्राकृतिक धागों से रेडीमेड गारमेन्ट पर सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। समय के साथ साथ पैकेज का प्रभाव पड़ा और क्षीणन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। सरकार ने दिसंबर 2017 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना अनुमोदित की।

- **चमड़ा क्षेत्र:** चमड़ा क्षेत्र अत्यंत श्रम आधारित क्षेत्र भी है। दिसंबर 2017 में चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए, 2600 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली स्कीम की तीन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-2020 के लिए घोषणा की गई।

- **रत्न और आभूषण:** भारत रत्नों और आभूषणों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि 2014-15 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 12.8 प्रतिशत हो गई है। इस क्षेत्र को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनके लिए आभूषण का डिजाइन तैयार करने, रिफाइनरी हॉल मार्क केन्द्र स्थापित करने आदि तथा विविध आभूषण पार्क तैयार करने में प्रशिक्षण के लिए सरकारी निजी भागीदारी अपेक्षित होगी।

अवसंरचनात्मक कार्य निष्पादन

1.61 भारत के दीर्घकालीन विकास में सहायता करने के लिए सरकार भवन अवसंरचना पर निवेश में बढ़ोतरी कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों के निष्पादन पर अगले पैराओं में चर्चा की गई है।

- **सड़क:** इस सेक्टर में सरकार के प्राथमिक एजेंडा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) बनाने और राज्य राजमार्गों (एसएच) को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की व्यवस्था है। सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में, 115,530 कि.मी. लम्बी सड़कें और राज्य राजमार्ग में 1,60,235 कि.मी. लम्बी सड़कें तथा 52,07,044 कि.मी. लम्बी अन्य सड़कें शामिल हैं। विलंबित परियोजनाओं के तुरन्त समापन के उद्देश्य से, भूमि अर्जन और पर्यावरण संबंधी अनुमति को सरल और कारगर बनाने के लिए विविध कदम उठाए गए हैं। नव व्यापक कार्यक्रम ''भारतमाला परियोजना'' का उद्देश्य एक आदर्श राजमार्ग विकास के लिए अनुकूल संसाधन नियतन प्राप्त करना है।

- **रेलवे:** अप्रैल-सितम्बर, 2017 के दौरान, भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की समरूपी अवधि के दौरान 531.2 मिलियन टन माल ढुलाई की तुलना में 558.1 मिलियन टन राजस्व अर्जक माल की ढुलाई की है जो इस अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार ने रेलवे अवसंरचना विकास पर जोर दिया है। ब्रॉड गेज (बीजी) लाइनों को चालू करने और विद्युतीकरण के कार्य समापन की गति को त्वरित किया गया है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से, दिंसबर, 2017 में, यथास्थिति, संपूर्ण भारत के विविध शहरों में 425 कि.मी. की मेट्रो रेल प्रणालियां चालू है और लगभग 684 कि.मी. की मेट्रो रेल प्रणाली निर्माणाधीन है।

- **पत्तन (बन्दरगाह):** वर्ष 2017-18 में (31-12-2017 तक) प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित कार्गो यातायात वर्ष 2016-17 की समान अवधि के दौरान संचालित 481.8 मिलियन टन कार्गो यातायात की तुलना में 499.4 मिलियन टन हो गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य भारतीय तट रेखा के किनारे पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है, 2.17 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 289 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

- **दूरसंचार:** 'भारत नेट' एवं 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रम भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए हैं। सितम्बर, 2017 के

अंत में, कुल ग्राहकों की संख्या 1207 मिलियन हो गई जिसमें से 502 मिलियन कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 705 मिलियन कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे।

- **नागर विमानन:** अप्रैल-सितम्बर, 2017 में, घरेलू एयरलाइनों में 57.5 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की जो पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। सरकार हवाई सेवाओं के उदारीकरण, विमानपत्तन विकास और उड़ान स्कीम के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव जैसी पहल कर रही है।

- विद्युत: अखिल भारतीय स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार 330,861 मेगावाट पहुंच गई है। 1 अप्रैल 2015 को यथास्थिति, कुल 18,542 गाँव अविद्युतीकृत थे जिनमें से 30 नवम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 15183 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) में ब्याज भार, बिजली की लागत और सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को को कम करके डिस्कामों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। सौभाग्य नामक एक नई स्कीम (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) सितम्बर, 2017 में प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाकी सभी इच्छुक परिवारों (घरों) का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था।

सेवाएं

1.62 भारत की सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) में 55.2 प्रतिशत के हिस्से के साथ सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक संवृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक बना हुआ है जो वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य की वृद्धि का लगभग 72.5 प्रतिशत है। यद्यपि वर्ष 2017-18 में इस क्षेत्र की संवृद्धि के 8.3 प्रतिशत होने की उम्मीद की जाती है, किन्तु सेवा निर्यातों और निवल सेवाओं में वृद्धि 2017-18 की प्रथम छमाही में क्रमश: 16.2 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

1.63 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जिनके लिए नव आधार (2011-12) सीरीज हेतु डेटा सीएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, उनमें से सेवा/सर्विस क्षेत्र 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य वृद्धि (जीएसवीए) के आधे से अधिक योगदानकर्त्ता प्रबल क्षेत्र है। इन 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, सर्विस क्षेत्र जीवीए शेयर के संदर्भ में दिल्ली एवं चंडीगढ़ सबसे ऊपर है जिनका हिस्सा 80 प्रतिशत है और सिक्किम सबसे नीचे है जिसका हिस्सा 31.7 प्रतिशत है।

1.64 वर्ष 2016-17 में, सेवा क्षेत्र (निर्माण सहित शीर्ष 10 क्षेत्र) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ईक्विटी अंतर्वाहों में 0.9 प्रतिशत कम होने पर वह 26.4 बिलियन अमेरिकी डालर रह गए हैं, भले ही, समग्र एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह 8.7 प्रतिशत तक बढ़ा है तथापि, वर्ष 2017-18 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की तुलना में इन क्षेत्रों के कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में, मुख्यत: दो क्षेत्रों अर्थात् दूरसंचार तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में उच्च एफडीआई के कारण, 15.0 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

1.65 वर्ष 2016 में भारत विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं में आठवां सबसे बड़ा निर्यातक (डब्ल्यूटीओ, 2017) रहा जिसका हिस्सा 3.4 प्रतिशत है और यह विश्व में भारत के पण्य निर्यातों के हिस्से का दोगुना है। भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वर्ष 2016-17 में 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ सकारात्मक क्षेत्र में लौट आयी जोकि वर्ष 2015-16 में (-)2.4 प्रतिशत थी। अप्रैल-सितम्बर 2017 के दौरान सेवा निर्यात में 16.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और यात्रा एवं सोफ्टवेयर सेवाओं जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कुछ मोड़ आया। भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यातों में भी अप्रैल-सितम्बर, 2017 में 17.4 प्रतिशत की अत्यधिक उच्च वृद्धि दिखाई दी। निवल सेवा प्राप्तियों में वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 के अप्रैल-सितम्बर के दौरान 14.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। सेवाओं में निवल बचत से वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में भारत के लगभग 49 प्रतिशत पण्य व्यापार घाटे का लिए वित्तीयन हो गया और इससे चालू खाता घाटे को सहारा मिला।

1.66 भारत में, आने वाले विदेशी पर्यटकों (एफटीए) की संख्या के वर्ष 2016 में 8.8 मिलियन तक पहुँचने के कारण पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2016 में विदेशी मुद्रा आय (एफ.ई.ई) में 22.9 बिलियन अमेरिकी डालर की आय में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम डाटा के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान 10.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2016 के दौरान पर्यटन संबंधी विदेशी मुद्रा आय में 27.7 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हॉल ही के वर्षों में पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2015 के दौरान भारत से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 20.4 मिलियन थी जो वर्ष 2016 के दौरान 7.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 21.9 मिलियन हो गई। यह संख्या भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के दोगुने से भी अधिक हैं। घरेलू पर्यटकों की संख्या जहां वर्ष 2015 में 1432 मिलियन थी वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या 12.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 1614 मिलियन हो गई।

1.67 एनएएसएससीओएम डाटा के अनुसार भारत की सूचना प्रौद्योगिकी-बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (आईटीबीपीएम) उद्योग में वर्ष 2016-17 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 139.9 बिलियन अमेरिकी डालर (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर के अलावा) हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान आईटी-बीपीएम निर्यात में साथ 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 116.1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ई-कामर्स बाजार में 33 19.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बिलियन अमरीकी डालर हो जाने का अनुमान लगाया गया। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात में 0.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में इसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईटी-आईटीईएस संबंधी कुल निर्यात में लगभग 90 प्रतिशत की भागीदारी अमेरीका, यूके तथा यूरोपीय संघ की रही। इन परंपरागत भौगोलिक परिस्थितियों में नई-नई चुनौतियों के आने से एशिया प्रशांत के देशों (एपीएसी), लेटिन अमरीका और मध्यपूर्व एशिया से मांग बढ़ने से महाद्वीपीय यूरोप, जापान, चीन और अफ्रीका में नए नए नए अवसरों का विस्तार हो रहा है।

1.68 स्थावर संपदा क्षेत्र, में (आवास स्वामित्व सहित) की वर्ष 2015-16 में भारत के समग्र जीवीए में 7.7 प्रतिशत की भागीदारी रही। गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्र के विकास में गिरावट आई है। जहां वर्ष 2013-14 के दौरान यह वृद्धि 7.5 प्रतिशत थी वहीं 2015-16 में यह घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई। इसका मुख्य कारण आवास स्वामित्व की वृद्धि में गिरावट का आना है। वर्ष 2013-14 में जहां यह वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2015-16 में गिरकर 3.2 प्रतिशत रह गई। एनएचबी के रेजीडैक्स इंडेक्स के अनुसार 50 मुख्य शहरों में से 36 शहरों में अप्रैल-जून 2017 के दौरान मकानों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी जब 13 शहरों में गिरावट दर्ज की गई।

1.69 वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित प्रोफेशनल वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलापों में क्रमश: 17.5 प्रतिशत और 41.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में कार्यरत अनुसंधान और विकास सेवा कंपनियों, जिनकी वैश्विक बाजार में भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है, में 12.7 प्रतिशत की रफतार से बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि अनुसंधान और विकास में भारत का कुल व्यय बहुत कम है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के केवल 1 प्रतिशत के लगभग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के मामले में भारत वर्तमान में 127 देशों की सूची में 60वें स्थान पर आ गया है जबकि वर्ष 2016 में 66वें स्थान पर था। ग्लोबल कंपीटिटिवनेस रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार इनोवेशन के संबंध में भारत की क्षमता अमेरिका, यूके, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों से बहुत कम है लेकिन चीन से बेहतर स्थिति में है। तथापि, प्रति मिलियन आबादी के हिसाब से पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत ब्रिक्स के अन्य देशों से बहुत अधिक पीछे है और अनुसंधान और विकास पर कंपनी खर्च के मामले में भारत चीन से मामूली पीछे है।

1.70 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में पीएलएलबी में 254 उपग्रहों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपत्र किया। उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में भारत की भागीदारी में भी 2014-15 में 0.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1.1 प्रतिशत हो गई।

1.71 सरकार ने विभिन्न सेवा क्षेत्रों, जैसेकि डिजीटलीकरण, ई-वीजा, संभार तंत्र संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, स्टार्ट अप इंडिया और हाउसिंग क्षेत्र आदि से संबंधित योजनाओं, में अनेक कदम उठाए हैं जिससे सेवा क्षेत्र में उछाल आने

की संभावना है। पर्यटन, विमानन और दूर संचार जैसे उप-सेक्टरों के अच्छे प्रदर्शन के कारण संभावनाएं उज्जवल प्रतीत हो रही हैं। तथापि, सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवा क्षेत्रों को बाहरी कारकों से उत्पन्न जोखिम मौजूद हैं।

सामाजिक अधिसंरचना:

सामाजिक अधिसंरचना पर व्यय

1.72 भारत में 2012-13 से 2014-15 के दौरान समाज सेवा पर किया जाने वाला व्यय जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में 6 प्रतिशत की रेंज में स्थिर रहा है तथा यह 2015-16 में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 (बी.ई.) में 6.6 प्रतिशत हो गया।

1.73 सभी 29 राज्यों द्वारा तीन वर्षों (अर्थात् 2014-15 से 2016-17 (बजट अनुमान) में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में समाज सेवा पर किया जाने वाला राज्यवार व्यय 6 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालाँकि, राज्यों के बजट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि समाज सेवा पर किए जाने वाले व्यय के अंश में अंतर-राज्य अंतर बहुत अधिक हैं। 2016-17 में अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, तथा जम्मू और कश्मीर ने समाज सेवा पर जीएसडीपी के सर्वाधिक अंश का व्यय किया है, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब और एनसीटी दिल्ली इस क्षेत्र में सबसे निचले स्थान पर रहा है।

शिक्षा की स्थिति

1.74 शिक्षा का अधिकार सूचकांक, जो शिक्षा की सर्वव्यापकता की प्रभावोत्पादकता को दर्शाता है, के अनुसार, अधिकांश राज्यों में पीटीआर (छात्र शिक्षक अनुपात) प्रतिमानकों द्वारा अनुपालित विद्यालयों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। जीपीआई (लैंगिक समानता सूचकांक) महिलाओं को शिक्षा देने में किए जाने वाले भेदभाव को दर्शाता है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के नामांकन में जीपीआई में काफी हद तक सुधार हुआ है। हालांकि, उच्च शिक्षा में नामांकन के क्षेत्र में लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है, जिसके संबंध में, उच्च शिक्षा में महिलाओं के निवल दाखिले की दर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

1.75 'भारत: देश के राज्यों का स्वास्थ्य' रिपोर्ट, 2017 में पहली बार वर्ष 1990 से 2016 तक की देश के सभी राज्यों से संबंधित बीमारियों और जोखिम घटकों पर निष्कर्षों का व्यापक सेट दिया गया है। कुपोषण अभी भी सर्वाधिक जोखिम घटक (14.6 प्रतिशत) है जिसका परिणाम देश में बीमारी बोझ के रूप में पड़ता है, भले ही इसमें वर्ष 1990 से पर्याप्त गिरावट आ रही है। भारत में कुल बीमारी बोझ का 33 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2016 में संक्रामक, मातृक, नवजात, और कुपोषण संबंधी बीमारियों (जिन्हें संक्रामक एवं अनुषंगी बीमारियां कहा जाता है) के कारण था। गैर संक्रामक बीमारियों के योगदान में वर्ष 1990 में 30 प्रतिशत कुल बीमारी बोझ वर्ष 2016 में बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है और चोट का योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। लगभग 5 प्रतिशत स्वास्थ्य हानि असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, और हाथ धोने की पद्धतियों के कारण थी जिसका निवारण सरकार स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन

1.76 कई अध्ययनों से पता चला है कि खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) क्षेत्र होने से स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में लाभ हुआ है। भारत को स्वच्छता सुविधाओं के अभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक की लागत वहन करनी पड़ती है। स्वस्थ जीवन में स्वच्छता की भूमिका को स्वीकार करते हुए और सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, अक्टूबर 2014 में खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या 55 करोड़ थी जो अक्टूबर, 2017 में घटकर 30 करोड़ रह गई; जोकि वर्ष 2014 से पूर्व देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में एक तीव्रतर गति से बदलाव हुआ है।

श्रम सुधार

1.77 भारत में रोजगार सेक्टर अपनी संरचना के अनुसार बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करता है जिस पर अनौपचारिक कामगारों, बेरोजगारी के उच्च स्तरों, कौशल की कमी तथा कठोर श्रम कानूनों और संस्थाओं

से युक्त श्रम बाजारों का प्रभाव है। इस संदर्भ में सरकार मौजूदा कानूनों के संगत प्रावधानों को तैयार कर चार श्रम संहिताएं यानी, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता तथा संरक्षा, एवं काम की दशाओं पर संहिता, बनाकर 38 श्रम अधिनियमों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है।

धारणीय विकास, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

धारणीय विकास लक्ष्य

1.78 भारत द्वारा चुने गए विकास पथ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित धारणीय विकास के लक्ष्यों के बीच बहुत सी समानताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जिन्हें सितंबर, 2015 में विश्व समुदाय द्वारा अंगीकृत किया गया है, में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है और इनमें सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसे कुल 17 एसडीजी हैं जिनके तहत वर्ष 2030 तक 169 लक्ष्य प्राप्त किए जाने निश्चित किए गए हैं।

1.79 न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में धारणीय विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) में 19 जुलाई, 2017 को एसडीजी के कार्यान्वयन पर भारत ने अपनी प्रथम स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत की। यह वीएनआर रिपोर्ट देश में विभिन्न कार्यक्रमों एवं कदमों के तहत हुई प्रगति के विश्लेषण पर आधारित है। वीएनआर रिपोर्ट में 7 एसडीजी पर फोकस किया गया, जो हैं एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन); 2 (शून्य भूख); 3 (उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर जीवन); 5 (लिंग-समानता); 9 (उद्योग, नवीकरण और अवसंरचना); 14 (जलीय जीवन) और 17 (लक्ष्यों हेतु साझेदारी)।

शहरी भारत और धारणीय विकास

1.80 एसडीजी 11 का नारा है, ''शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और धारणीय बनाएं''। भारत अब ग्रामीण से शहरी जीवन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज की सबसे जरूरी मांग यह है कि शहरों के निवासियों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएं। हालांकि, धारणीय शहरी रूपांतरण के लिए आवश्यक परिमाण में संसाधनों की प्राप्ति एक भयंकर चुनौती सिद्ध हो रही है। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में औसत लागत वसूली 50 प्रतिशत से कम है। इसके आगे विभिन्न नवीन वित्तीय साधनों जैसेकि म्यूनिसिपल बाँड्स, पीपीपी, क्रेडिट जोखिम गारंटी आदि के माध्यम से संसाधन जुटाने में यूएलबी के समक्ष उत्पन्न चुनौती से निपटने की बात है।

धारणीय ऊर्जा की उपलब्धता

1.81 वहनीय विश्वसनीय, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच का अन्य समस्त लक्ष्यों के साथ गहरा अंतर्संबंध है। यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर अन्य धारणीय विकास उद्देश्यों, जैसेकि उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन, लैंगिक समानता, उद्योग, नवीकरण और अवसंरचना धारणीय शहर एवं समुदायों आदि से भी संबंधित है।

1.82 भारत में परिवारों की महिलाएं सदस्यों पर जलावन लकड़ी और पानी लाने और खाना पकाने का बोझ गैर आनुपातिक रूप से अधिक रहा है। जो महिलाएं और बच्चे खाना बनाने के कार्य में सीधे लगे हुए हैं अथवा जिनका अत्यधिक समय घरों में ही व्यतीत होता है उन पर घर के भीतर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों में भी गैर आनुपातिक रूप से गिरावट आ रही है। यद्यपि अनेक वर्षों में देश में स्वच्छ भोजन पकाने के विकल्पों तक परिवारों की पहुंच मुहैया कराने में पर्याप्त प्रगति हुई है, फिर भी अभी भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक है जिनकी पहुंच भोजन पकाने के स्वच्छ ईंधनों तक नहीं है। इस प्रकार से आधुनिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित होने से जलावन लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए नष्ट हुए समय को कम किया जा सकता है और ऐसा करके बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है।

1.83 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पिछले संस्करण में रिपोर्ट दी गई है, भारत सरकार ने मई, 2016 में ''प्रधान मंत्री उज्जवला योजना'' (पीएमयूवाई) शुरू की थी और इसे उन्नत किया गया है जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वर्ष 2020 तक 80 मिलियन एलपीजी कनेक्शन दिए जा सकें। उपर्युक्त स्कीम को पूरा करने के लिए सरकार ''उज्जवला प्लस'' नामक अन्य पहलों को भी लाई है। जिससे ऐसे वंचित व्यक्तियों की रसोई संबंधी आवश्यकताओं का निवारण होगा जो सामाजिक आर्थिक जाति गणना (एसईसीसी) 2011 के तहत नहीं आते हैं। वर्ष

2016-17 के दौरान 3.25 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए थे जिसमें प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत जारी किए गए 2 करोड़ कनेक्शन भी शामिल हैं।

1.84 इसके अलावा, भारत सरकार 2019 तक सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विश्वसनीय और गुणवत्ता बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2015 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम की शुरूआत की गई थी और देश के ग्रामीण और शहरी प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली रहित सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 25 सितम्बर, 2017 को सौभाग्य स्कीम शुरू की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पोर्टल सौभाग्य के अनुसार देश के 18.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.2 करोड़ (78 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में बिजली पहुंचा दी गई है (16 जनवरी, 2018 की यथास्थिति)। भारत की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में से 18 प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों प्राप्त की गई थी (30 नवंबर, 2017 की यथास्थिति)।

1.85 इंटरनेशनल सोलर एलाइंस (आईएसए) का प्रभावी होना: 30 नवम्बर 2015 को भारत के माननीय प्रध ान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रैंकोइस होलांडे द्वारा शुरू किए गए आईएसए ने 6 दिसम्बर 2017 से कार्य प्रारंभ कर दिया। आईएसए सौर संसाधनों से सम्पन्न राष्ट्रों का संगठन है जो पूर्णत: या अंशत: कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का दोहन करके ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है। आईएसए पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आध ारित संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। आज की तारीख में 46 देश इस पर सहमति दर्ज करा चुके हैं जिनमें से 19 देशों ने आईएसए फ्रेम वर्क एग्रीमेंट का अनुसमर्थन किया है। आईएसए में सौर ऊर्जा के लिए ट्रिलियन डालर के अवसर मौजूद हैं। परिणाम स्वरूप 121 आईएसए सदस्य देशों में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों से अर्थव्यवस्था और उद्योग दोनों को लाभ हो सकता है।

भारत और जलवायु परिवर्तन

1.86 भारत ने घरेलू स्तर पर अपनी पर्यावरणीय कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं और संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। भारत सरकार विविध अन्य प्रयासों के अलावा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सौर, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल, सतत् पर्यावास, वानिकी हिमालय पारिस्थितिकी की प्रणाली तथा ज्ञानयुक्त आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन कार्यों से पर्यावरण परिवर्तन संबंधी समस्या का सामना करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता प्रतिबिंबित होती है।

जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान बहुपक्षीय वार्ताएं

1.87 वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता मुख्यत: पेरिस करार को लागू करने के लिए नियमों एवं विनियमों को बनाने पर केंद्रित है। यूएनएफसीसीसी (सीओपी 23) में पक्षकार देशों के सम्मेलन के 23वें सत्र में इन देशों ने पेरिस करार के अधीन कार्य से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भारत के लिए सीओपी 23 की मुख्य उपलब्धि यह रही की 2020 के पूर्व जलवायु परिवर्तन के एजेंडा से संबंधित प्रतिबद्धताएं और कार्यान्वयन को सीओपी 23 के निष्कर्षों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि 2020 से पूर्व कार्रवाई एवं योजना पर भावी कदम उठाए जाएं। इस निर्णय में 2020 से पूर्व की विस्तारित योजना पर जोर दिया गया है जोकि 2020 के बाद की विस्तारित योजना के लिए मजबूत आधार रख सकता है। भारत पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम के विभिन्न तत्वों पर अनौपचारिक टिप्पणियों/पाठों पर अपने मत को स्थापित करने में सफल रहा है जिसमें पेरिस करार के लिए राष्ट्रीय अंशदान, अनुकूलन संचार, निष्पक्षता ढांचा, अनुपालन, प्रौद्योगिकी ढांचा, वित्त और नियमों, पद्धतियों और दिशा-निर्देशों के समता निर्माण भी सम्मिलित हैं।